नवंबर-2025 | वर्ष : 09 | अंक : 08 | मूल्य : ₹25/- मात्र

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

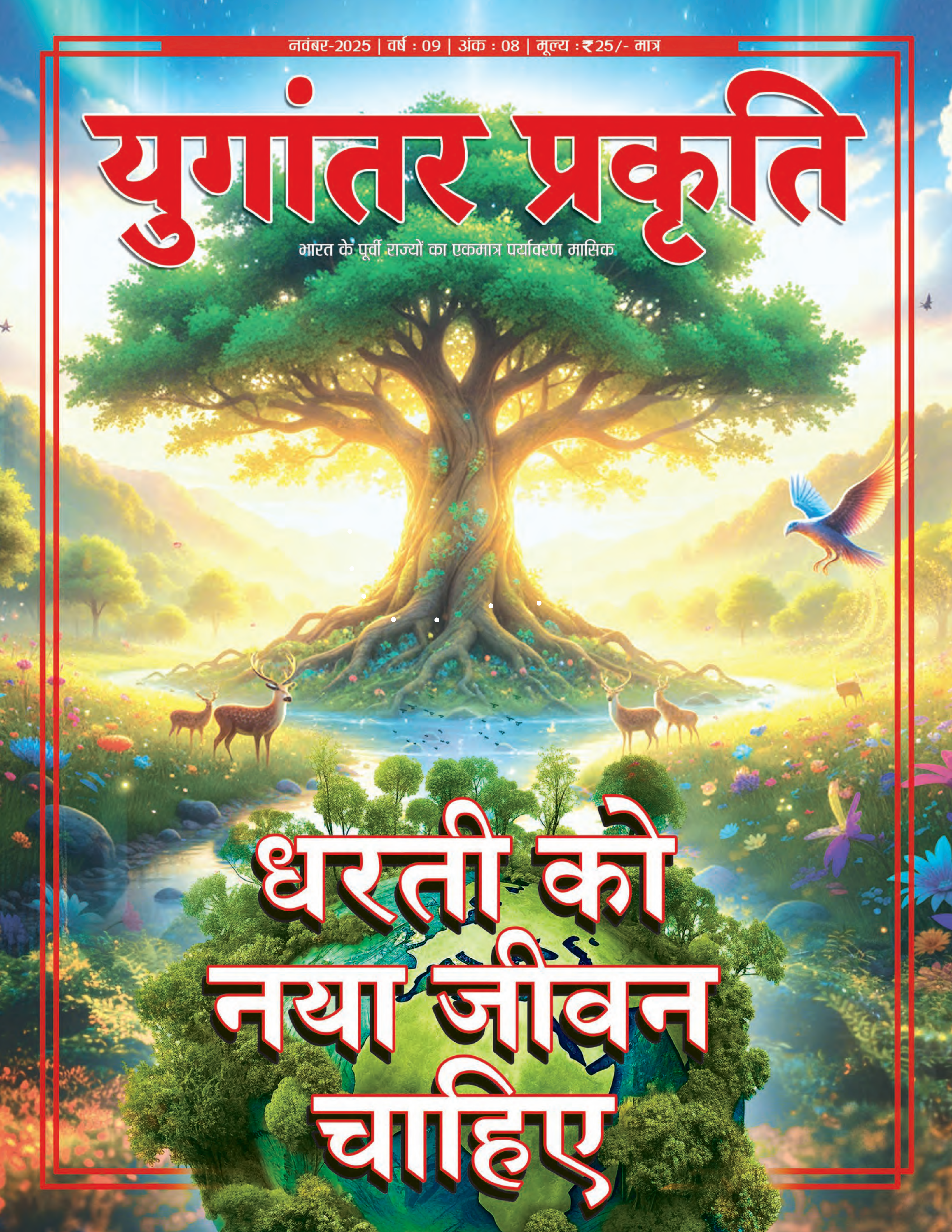

धरती को नया जीवन चाहिए

युगांतर प्रकृति

प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित मासिक पत्रिका

प्रकृति, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान, क्षमता संवर्धन शोध एवं विकास तथा राष्ट्रीय गौरव के लिए समर्पित संस्था

सदस्यता शुल्क

1	वार्षिक	250/-
2	पंचवर्षीय	1,200/-
3	दस वर्षीय	2400/-
4	आजीवन	5,000/-

विज्ञापन दर

1	बैक पेज	1,00,000/-
2	इनसाइड कवर पेज	90,000/-
3	फुल पेज	75,000/-
4	हाफ पेज	50,000/-

भुगतान संबंधित निर्देश

भुगतान कृपया चेक/डीडी/आरटीजीएस द्वारा Nature Foundation के नाम से करें

Account Details

NATURE FOUNDATION

Account No. : 3611740792
Kotak Mahindra Bank
IFSC Code : KKBK0005631

विज्ञापन संबंधित निर्देश

कृपया अपना विज्ञापन पीडीएफ अथवा जेपीजी फॉर्मेट में yugantarprakriti@gmail.com ईमेल या डाक द्वारा युगांतर प्रकृति, सेंट्रल स्कूल के समीप, सिद्रोल, नामकुम, रांची-834010 के पते पर भेजें।

विशेष सहयोग

'युगांतर प्रकृति' का प्रकाशन नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। पत्रिका के सुगम प्रकाशन हेतु Nature Foundation के नाम चेक अथवा डीडी के माध्यम से यथासंभव आर्थिक सहयोग आमंत्रित है।

इस अंक में खास...

08 धरती को नया जीवन चाहिए

18
अवैध खनन
पलामू में अवैध खनन पर एनजीटी खफा

22
स्पेशल स्टोरी
हाथी आबादी का संकट और संरक्षण की उम्मीद
झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की संख्या घटकर महज 10 रह गई है। यह खबर न केवल स्थानीय निवासियों को चिंतित कर रही है, बल्कि वन्यजीव प्रेमियों के बीच एक बहस छेड़ रही है।

03
विशेष रिपोर्ट
सारंडा के 31468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को ही सैंक्चुरी घोषित करें
सारंडा को वन अभ्यारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आकार छोटा किया है, साथ ही सेल को खनन में दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा है।

12
ग्रीनहाउस
ग्रीनहाउस गैसों ने तोड़े रिकॉर्ड
वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा ही कुछ 2024 में भी दर्ज किया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का वार्षिक औसत स्तर बढ़कर 423.9 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गया।

14
स्वास्थ्य पर्यावरण

अस्थमा वाला इनहेलर पर्यावरण के लिए खतरा

31
कला जगत
रतन टाटा, अमिताभ बच्चन और शिबू सोरेन की पेंटिंग बना कर भी मैं जमीन पर हूं-अर्जुन दास

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

वर्ष-9, अंक-08, नवंबर-2025, कुल पृष्ठ-36 (आवरण सहित)

मुख्य संरक्षक
सरयू राय

प्रधान संपादक
आनंद सिंह

संपादक
अंशुल शरण

संरक्षक मंडल
राजेन्द्र सिंह, एम.सी. मेहता, प्रो. आर. के. सिन्हा, प्रो. एस. इ. हसनैन, डॉ. आर. एन. शरण, डॉ. आर. के. सिंह

सलाहकार मंडल
डॉ. एम. के. जमुआर, डॉ. दिनेश कुमार मिश्र, डॉ. के. के. शर्मा, डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ. ज्योति प्रकाश

डिजाइन आर्टिस्ट
अनवारूल हक

विधि परामर्शी
रवि शंकर (अधिवक्ता)

प्रबंधन
राजेश कुमार सिन्हा

संपादकीय कार्यालय
संपादकीय, सदस्यता एवं विज्ञापन
नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप
पो. नामकूम, सिदरौल, रांची, झारखंड, पिन-834010

कोलकाता कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, 131/24, रीजेंट पार्क गवर्नमेंट क्वार्टर, कोलकाता, पिन-700040

पटना कार्यालय
201, दीपराज कॉम्प्लेक्स, आर्य कुमार रोड, दिनकर गोलंबर, पटना 834004

स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक **मधु** द्वारा झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि., 6A, गुरुनानक नगर, साकची, **जमशेदपुर** से मुद्रित व नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप पो. नामकूम, सिदरौल, **रांची**, झारखंड से प्रकाशित।
आरएनआई नंबर: JHAHIN/2016/68667
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर: RN/248/2016-18

ई-मेल: yugantarprakriti@gmail.com
मोबाइल 7307071539, 9304955301/2

■अपनी बात

■ अंशुल शरण

शाकाहार अपनाएं

नमस्कार,

दुनिया के प्रायः सभी देशों में एक अक्तूबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। समस्त दुनिया को निरोगी रहने के लिए शाकाहार का जम कर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

यह ठीक भी है। मांस-मछली आज के इस दौर में पचने में बहुत वक्त लेते हैं। ये अधिकांश समय तक हमारी अंतड़ियों में जमा रहते हैं, जिससे पाचन क्रिया में दिक्कत होती है।

शाकाहारी भोजन भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। नॉन वेज पहले भी लोग खाते थे, आज भी खाते हैं और भविष्य में भी खाते रहेंगे लेकिन मांसाहार से शाकाहार की तुलना संभव नहीं।

मेडिकल साइंस में कई शोध हुए और यह साबित हुआ कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार शरीर, दिमाग आदि के लिए ज्यादा मुफीद है।

एक दौर में मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी नॉनवेज के शौकीन थे लेकिन वह पिछले कई दशकों से शुद्ध शाकाहारी हैं। अमिताभ बच्चन के साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी शुद्ध शाकाहारी हैं।

एक दौर था, जब मांसाहार को प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन, कार्डियेक अरेस्ट, हृदयाघात, पार्किंसन, ब्लड प्रेशर, पक्षाघात जैसी बीमारियों के बारे में जब शोध किया गया तो मांसाहार बड़ा कारण निकला।

कोई भी मांसाहार हो, वह कैलस्ट्रोल को बढ़ाता है। कैलस्ट्रोल पूरी बॉडी का मेंटिनेंस बिगाड़ कर रख देता है। अब तो डॉक्टर भी रेड मटन के लिए मना करते हैं।

शाकाहारी भोजन के कई फायदे हैं। पहला, ये पचने में आसान होते हैं। दूसरा-ये सस्ते होते हैं। तीसरा-इनमें वेरायटी काफी होती है। चौथा-ये हर मौसम में उपलब्ध होते हैं। पांचवां-ये प्रायः शुद्ध होते हैं।

जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर उपजाने वाले खाद्य पदार्थ शरीर के साथ सामंजस्य बना लेते हैं। भारतीय शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। ये हैः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।

ये पंच तत्व आपकी काया को चलायमान बनाने में सहायक होते हैं और शाकाहार भी इन्हीं पंच तत्वों को समर्थन देता है।

पृथ्वी के ऊपर या नीचे आप जो भी फसल-सब्जी-फल लगाते हैं, वो कभी नुकसान नहीं करता। ऐसे ही, जिन पौधों में, सब्जियों में आप जल डालते हैं, वह भी कभी नुकसान नहीं करता।

ऐसे ही अग्नि, वायु और आकाश हैं, जो मानव मात्र के लिए हर तरह से कल्याणकारी होते हैं।

शाकाहारी लोगों के बारे में कई बार इस किस्म के शोध आए हैं, जिनमें उनके बारे में कहा गया है कि वे ज्यादा मजबूत, निरोगी, दीर्घजीवी, आत्मविश्वासी और चुनौतियों को स्वीकार करने वाली क्षमता से परिपूर्ण होते हैं।

मांस का भक्षण करने वालों के बारे में कहा गया है कि वे लड़ाकू, चिड़चिड़े, अल्पायु वाले, कमजोर और उचित फैसला नहीं करने वाले होते हैं।

शाकाहार की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। आप किसके इंतजार में हैं....

आपका ही

(अंशुल शरण)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सारंडा के 31468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को ही सैंक्चुरी घोषित करें

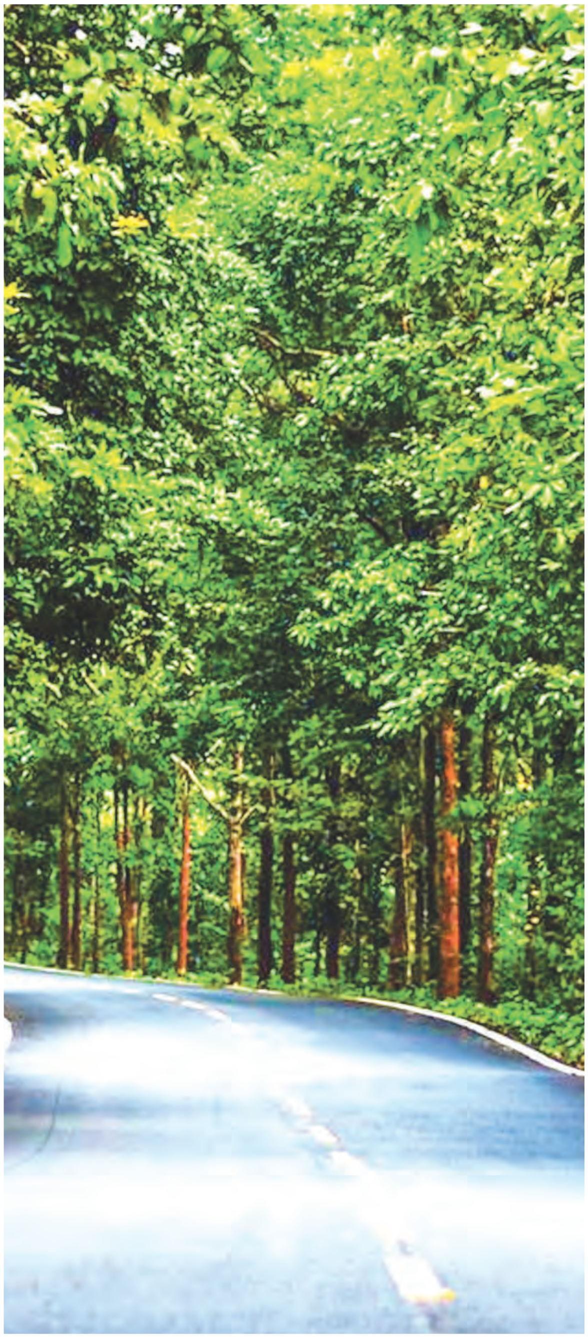

सारंडा को वन अभ्यारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आकार छोटा किया है, साथ ही सेल को खनन में दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा है। सेल ने अपील की थी कि वह सरकारी कंपनी है और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए स्टील की सप्लाई करती है। इसलिए उसका खनन प्रभावित नहीं होना चाहिए।

▪ युगांतर प्रकृति नेटवर्क/एजेंसियां

सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्तूबर को हुई सुनवाई में 57519.41 हेक्टेयर की जगह अब 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा अन्य और वैध माइनिंग लीज को सैंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है।

बिना सरकार की सहमति के दिया था शपथ पत्र

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एनजीटी के दिशा-निर्देश के आलोक में 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुअरी घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कोर्ट सरकार को 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे। इससे खनन प्रभावित ना हो, इसका आकलन कर 31468.25 को चिह्नित करने की अनुमति दी जाए।

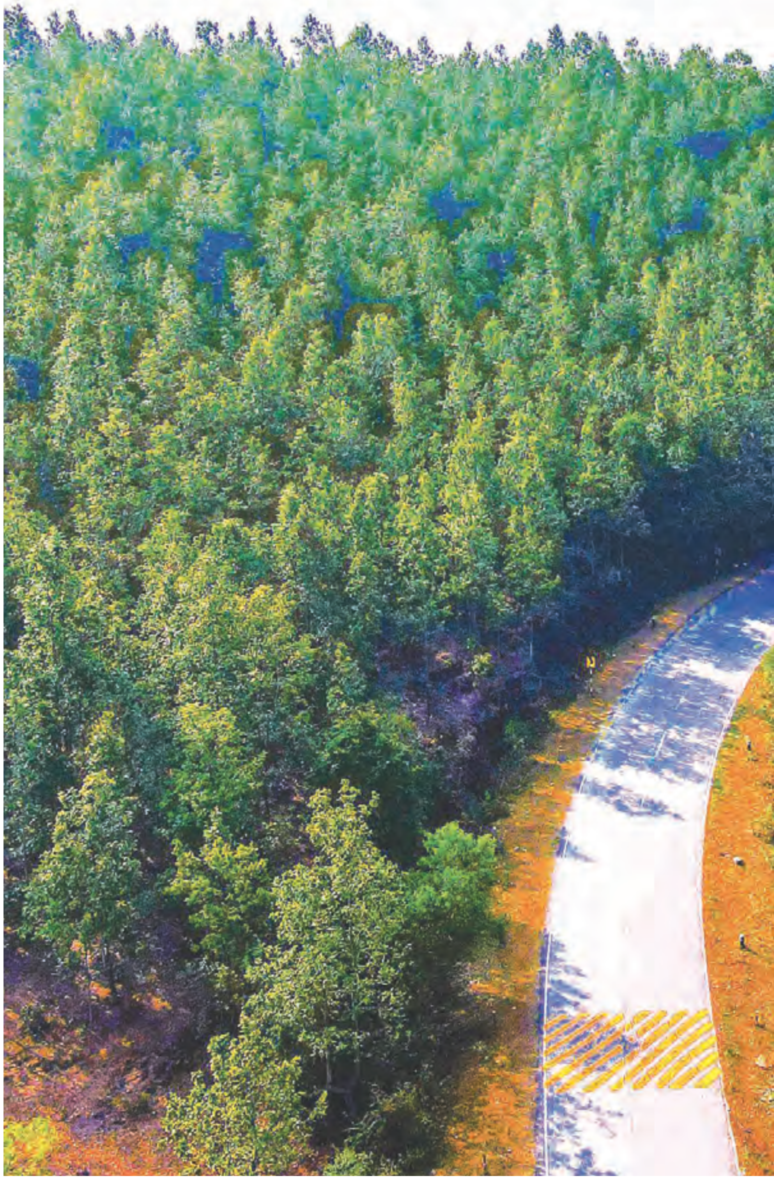

सबसे पहले सेल ने रखा अपना पक्ष

कोर्ट में सबसे पहले सेल की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सैंक्चुअरी घोषित करने के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। सेल की ओर से कहा गया कि सारंडा के खदान से उसके लौह अयस्क की जरूरतों का 50 प्रतिशत पूरा होता है। वह सरकारी कंपनी है। कंपनी 1947 से माइनिंग कर रही है और रेलवे, डीआरडीओ और इसरो को स्टील की सप्लाई की जाती है। चंद्रयान के लिए भी स्टील सप्लाई की गयी थी।

माइनिंग प्रभावित न हो

सेल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि न्यायालय इस बात का ध्यान रखने की अनुमति दे कि सैंक्चुअरी घोषित करने से सेल का माइनिंग प्रभावित न हो। कोर्ट ने स्टील उत्पादन और सेल द्वारा राष्ट्रीय महत्व की चीजों में स्टील की आपूर्ति करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया कि सैंक्चुअरी घोषित करने के दौरान माइनिंग प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर से होने से मुक्त कर दिया।

> **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 जुलाई 2022 को सारंडा में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने सारंडा के 400 वर्ग किमी क्षेत्र को ही अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया था। जब राज्य सरकार की ओर से इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, तब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।**

अभ्यारण्य बनाने के पक्षधर नहीं विभाग

वन एवं पर्यावरण विभाग ने पूरे सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने को लेकर खान-भूतत्व और उद्योग विभाग से मंतव्य मांगा था। ये दोनों विभाग पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के पक्ष में नहीं हैं। इन विभागों का कहना है कि पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाना राज्य के लिए नुकसानदेह होगा।

कैबिनेट के लिए तैयार प्रस्ताव में वित्त विभाग ने भी इन दोनों विभागों की राय पर सहमति जताई है। कहा है कि ऐसा होने से माइनिंग रॉयल्टी की संभावना भविष्य में और जटिल हो जाएगी। इन विभागों का कहना है कि सरकार राज्यहित में बीच का कोई रास्ता निकाले।

पूरा मामला ये है

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 जुलाई 2022 को सारंडा में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने सारंडा के 400 वर्ग किमी क्षेत्र को ही अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया था। जब राज्य सरकार की ओर से इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, तब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा। इसके बाद 29 अप्रैल को सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया।

वन विभाग की ओर से दायर हलफनामा में बताया गया कि राज्य सरकार 31468.25 हेक्टेयर के एनजीटी के मूल प्रस्ताव की जगह 57519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है। 13.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ससांगदाबुरु संरक्षित रिजर्व क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है।

सरकार कहां फंस रही है

दरअसल, वन विभाग के सचिव ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, वह पूर्व पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) सत्यजीत कुमार की ओर से तैयार प्रस्ताव है। पूर्व पीसीसीएफ ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 500 वर्ग किलोमीटर को अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा जबकि एनजीटी ने केवल 400 वर्ग किमी को भी अभ्यारण्य बनाने को निर्देश दिया था। पूर्व पीसीसीएफ ने अपने इस प्रस्ताव को लेकर न तो सरकार से कोई मंतव्य लिया और न ही विभागीय सचिव को जानकारी

दी। जब सरकार को इस बात की जानकारी हुई तो खान विभाग ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि ऐसा करने से सारंडा क्षेत्र में चल रही लौह अयस्क परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। पूरे चाईबासा क्षेत्र में 90 से अधिक लौह अयस्क खदान हैं, जिसमें करीब चार बिलियन टन का रिजर्व भी है। यहीं से यह मामला सरकार के खिलाफ चला गया।

मंत्रियों की कमेटी

जब मामला सरकार के खिलाफ चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी कि तब सरकार ने पांच सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। इस ग्रुप की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं। अन्य मंत्रियों में दीपिका सिंह पांडेय, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार सोनू और दीपक बरूआ शामिल हैं। अब तक टीम दो इलाकों का दौरा कर चुकी है।

गत 4 अक्टूबर को नंदपुर में आमसभा करने का कार्यक्रम तय था। लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण यह दौरा स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि 30 सितंबर को भी जब मंत्रियों की टीम सारंडा पहुंची थी, उस समय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया था। उस दौरान भी ग्रामीणों ने अभ्यारण्य बनाए जाने का पुरजोर विरोध जताते हुए कहा था कि यह उनकी संस्कृति और जीवनशैली पर हमला है।

विभिन्न विभागों की ये थी राय

खान विभागः खान विभाग ने अपनी राय में कहा है कि सारंडा वन क्षेत्र के करीब 26 फीसदी हिस्से में लौह अयस्क का भंडार है। यहां करीब 4700 मिलियन टन लौह अयस्क है, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे राज्य सरकार को करीब 14 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल सकती है। अगर इस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जाता है तो सभी परिचालन खत्म हो जाएंगी। इससे खनिज की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। राज्य में सालाना करीब 20 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अभ्यारण्य घोषित होने से उत्पादन घटेगा। रॉयल्टी सेस ओर डीएमएफटी के लिए होने वाले कलेक्शन में सालाना 5000 से 8000 करोड़ रुपए की नुकसान होगी । इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

> **वन एवं पर्यावरण विभाग ने पूरे सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने को लेकर खान-भूतत्व और उद्योग विभाग से मंतव्य मांगा था। ये दोनों विभाग पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के पक्ष में नहीं हैं। इन विभागों का कहना है कि पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाना राज्य के लिए नुकसानदेह होगा।**

उद्योग विभाग : उद्योग विभाग ने लिखा है कि पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने से वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में परेशानी होगी। सारंडा के लौह अयस्क भंडार से टाटा स्टील, सेल और निजी खनन कंपनियां चल रही हैं। इस क्षेत्र के खान एवं उद्योग से करीब 4।20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इलाके में 2000 एमएसएमई इकाइयां भी हैं। ऐसे प्रस्ताव से औद्योगिक विकास, राजस्व और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यहां से होने वाला 4400 करोड़ रुपए का निर्यात भी प्रभावित होगा। सारंडा एशिया के सबसे समृद्ध लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां करीब 2420 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। जिसका नुकसान हो जाएगा।

वित्त विभाग : इन दोनों विभागों की राय जानने के बाद वित्त विभाग ने लिखा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग और उद्योग विभाग ने आपत्तियां दर्ज की है। खान एवं भूतत्व विभाग ने कैरिंग कैपेसिटी के अध्ययन पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का विरोध किया है। इससे आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी। वित्त विभाग ने अपने मंतव्य में लिखा है कि तैयार प्रस्ताव स्वीकृत होने से खनन विभाग द्वारा संभावित माइनिंग रॉयल्टी की संभावना भविष्य में और भी जटिल हो जाएगी। इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होने से राजस्व प्राप्ति की संभावना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ■

तीन सारंडा वर्किंग प्लान्स बने हैं उनका अध्ययन करे सरकार: सरयू

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने दो टूक कहा है कि सारंडा के संबंध में झारखंड सरकार को स्पष्ट प्रतिवेदन जनता के सामने रखना चाहिए। भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। सारंडा सघन वन क्षेत्र में लौह अयस्क खनन के साथ ही पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों, जैव विविधताओं आदि का संरक्षण करने को प्राथमिकता देने की बात होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस बारे में भ्रम की स्थिति में है। राज्य सरकार को सरकार के भीतर वन, खान, उद्योग, वित्त विभागों के भीतर व्याप्त विरोधाभास को दूर करना चाहिए।

▪ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

सरयू राय ने कहा कि सारंडा में लौह अयस्क का खनन 1909 से हो रहा है. सारंडा के बारे में वन विभाग ने अबतक तीन महत्वपूर्ण वर्किंग प्लान तैयार किया है. पहला वर्किंग प्लान 1936 से 1956 तक के लिए एसएफ मुनी का बनाया हुआ है। दूसरा वर्किंग प्लान 1956 से 1976 तक चला, जिसे जेएन सिन्हा ने बनाया था। तीसरा वर्किंग प्लान 1976 से लेकर 1996 तक चला, जिसे राजहंस ने बनाया था। सरकार को चाहिए कि तीनों वर्किंग प्लान का अध्ययन करे और यह भी बताए कि 1996 के बाद सारंडा के लिए कोई वर्किंग प्लान राज्य सरकार ने क्यों नहीं बनाया? इन तीनों वर्किंग प्लान में विस्तार से सारंडा में वन भूमि के संरक्षण और खनन गतिविधियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा है।

सारंडा के संदर्भ में 7 जरूरी प्वाइंट्स

पहला : सारंडा सघन वन क्षेत्र में मौजूद साल का पेड़ का महत्व स्टील से कम नहीं है। एक कहावत है साल के बारे में 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर भी जौ बराबर भी नहीं सड़ा।

दूसरा : 2003 में भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट ने सभी राज्यों को वनों के संरक्षण के बारे में पत्र लिखा। उसके आधार पर झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने तीन-चार वर्षों तक अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित मधु कोड़ा की सरकार थी, उस समय के वन मंत्री सुधीर महतो ने सरकार के सामने सारंडा में अभग्न क्षेत्रों को घोषित करने का प्रस्ताव भेजा। अभग्न क्षेत्र का अर्थ है कि इनमें कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी, जिससे वन को नुकसान हो। सारंडा का कुल क्षेत्रफल करीब-करीब 851 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से सुधीर महतो के नेतृत्व में 630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभग्न क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को 2009 में भेजा गया। सरकार ने आज तक उस प्रस्ताव को न तो नकारा और ना ही स्वीकार किया। इसके पीछे का क्या कारण है?

तीसरा: जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे तो उस समय इतने माइनिंग लीज के आवेदनों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि सभी का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो यह सारंडा के कुल क्षेत्रफल से अधिक हो जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने तभी यह मामला उठाया था, जिसमें अवैध खनन भी था।

चौथा: भारत सरकार ने 2010 में रिटायर्ड जस्टिस एम बी शाह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में झारखंड में अवैध खनन के बारे में और वनों के संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया.

पाँचवां: तदुपरांत 2011 में भारत सरकार के निर्देश पर झारखण्ड सरकार ने इंटीग्रेटेड वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति ने साल भर के बाद रिपोर्ट दी। इस समिति की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें लौह अयस्क खनन के संदर्भ में वन्यजीवों के संरक्षण और वनों

के संरक्षण का विस्तृत उल्लेख है।

छठाः इसके बाद भारत सरकार ने 2014 में सारंडा का कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अध्ययन के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञों का समूह बनाया. इस समूह ने सारंडा वन क्षेत्र में खनन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया कि ऐसी कितनी आर्थिक गतिविधियों का बोझ सारंडा बर्दाश्त कर पाएगा। इस प्रतिवेदन पर भी सरकार चुप रही। कुछ नहीं किया।

सातवांः इसके बाद भारत सरकार ने एक और कमेटी माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबुल माइनिंग के लिए बनाया.

इस समिति ने रिपोर्ट दिया कि सारंडा में इस तरह से माइनिंग हो कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी हो। इसने सारंडा के नक़्शे पर माइनिंग ज़ोन एवं नो माइनिंग ज़ोन चिन्हित किया. इन सभी उच्च स्तरीय समितियों के प्रतिवेदनों का सरकार अध्ययन करे और तब निष्कर्ष पर पहुंचे।

सरयू राय ने कहा कि अब तक सारंडा में जितने क्षेत्रों में लौह अयस्क खनन हुआ है, उन सभी को माइनिंग ज़ोन में रखा गया है। यहां माइनिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिवर्ष औसतन 25 मिलियन टन लौह अयस्क का खनन यहां होते रहा है। इस तरह अगले 50 वर्षों तक के लिए यहां पर्याप्त लौह अयस्क भंडार है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार के खान विभाग के पास लौह अयस्क खनन क्षेत्र का जी-2 आँकड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में निवेशक यहां खनन के लिए आने के पहले सौ बार सोचेंगे। लौह अयस्क खनन का सारंडा वन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, खनन करनेवालों ने सरकार के नियमों का कितना पालन किया और कितना उल्लंघन किया, इसके बारे में सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

सरयू राय ने आरोप लगाया कि सारंडा में सर्वाधिक लौह अयस्क का खनन लीज भारत सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लमिटेड (सेल) के पास है. यह सारंडा में लौह अयस्क खनन करने वाली सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। यह कंपनी भी सारंडा सैंक्चुअरी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई है जिसपर सुनवाई चल रही है। जितना अत्याचार सेल ने सारंडा पर माइनिंग के दौरान किया है वह माफी के लायक नहीं है। इसने लौह अयस्क का ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से करने का वादा किया पर आज तक बेल्ट के माध्यम से एक फीट भी ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया गया। उल्टे चिंडिया से मनोहरपुर रेलवे स्टेशन तक का जो वन पथ है, उस बंद पथ को बिना पर्यावरण स्वीकृति लिए सेल ने चौड़ा कर दिया है और यातायात का मुख्य लिए कॉरिडोर दिया है। इसके कारण वनों को, वन्य जीवों को और वहां के लोगों को भारी नुकसान हुआ है।

सरयू राय ने बताया कि झारखंड में दो बड़ी नदियां हैं। कारो और कोयना। दोनों ही नदियां लौह अयस्क खनन से बुरी तरह प्रदुषित हो चुकी हैं। नदियों का पानी बिल्कुल लाल हो गया। जब सारंडा में उग्रवादी गतिविधियां प्रबल थीं तो एक सवाल उठ रहा था कि लाल सलाम ज्यादा खतरनाक है या लाल पानी? सभी मानते थे कि लाल पानी ज्यादा खतरनाक है। लोग इसका इस्तेमाल करते थे, पशु-पक्षी इस्तेमाल करते थे। यह अब प्रदूषित हो गया है।

सरयू राय ने कहाः अभी सवाल यह है कि पूरा सारंडा रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में सैंक्चुअरी नहीं घोषित होगी तो भी यहां जो माइनिंग होगी, उस पर भारत सरकार के सारे नियम कानून लागू होंगे। एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेना होगा, फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेना होगा, फॉरेस्ट एडवायजरी कमेटी की अनुशंसा लेनी होगी, पर्यावरण, वन मंत्रालय का आदेश लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल सारंडा सैंक्चुअरी प्लान में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय निवासी के सभी वनाधिकार जस का तस रहेंगे।

यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कंडिका 26ए का उल्लेख प्रासंगिक होगा जिसमें कहा गया हैं कि आवश्यक होने पर नेशनल बोर्ड की अनुमति से सैंक्चुअरी के बाउंड्री में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर सैंक्चुअरी बनने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा हाय तौबा मचाने का कारण क्या है?

देश के 4-5 बड़े माइंस होल्डर हैं, जिनका सारंडा में लौह अयस्क खनन लीज लेने का आवेदन राज्य सरकार ने आज से 15 साल पहले भारत सरकार को भेजा है। उसमें जेएसडब्ल्यू है, जेएसपीएल है, मित्तल उद्योग है, टाटा स्टील है, इलेक्ट्रो स्टील है। सारे लोगों का जिस क्षेत्र में आवेदन है, उसके बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्यों इन्हें एनजीटी से खनन स्वीकृति क्यों नहीं मिल पा रही है।

सरयू राय ने यह भी कहा कि सेंक्चुअरी को विवाद में लाने के बदले में सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वह और उनके जैसे तमाम लोग इस मत के हैं कि सस्टेनेबुल माइनिंग होनी चाहिए। सस्टेनेबुल माइनिंग डेवलपमेंट प्लान बन गया है। उसमें सविस्तार लिखा गया है कि कैसे सस्टेनेबुल माइनिंग होगी। इसके बारे में सरकार मौन क्यों है।

सरयू राय ने कहा है कि 2017 में भारत की सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स

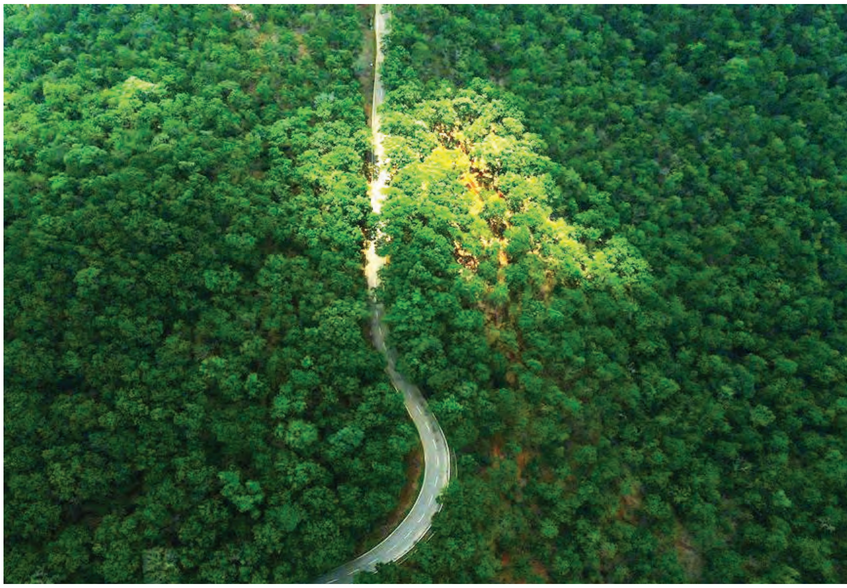

डेवलपमेंट रेगुलेशन में संशोधन किया। उस संशोधन के आधार पर जो ऐसी खदानें थी, जिनका लीज था, क्योंकि वह व्यापार करते हैं। उनका खनन लीज मार्च 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया। जिनकी अपनी फैक्ट्री है, जैसे टाटा स्टील सेल आदि, इनका भी खनन लीज अब 31 मार्च 2030 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सारी खदानों का लीज ऑक्शन के आधार पर होगा। अब जिनका लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया, पड़ोस के उड़ीसा में 1 साल के भीतर सभी लीजों का ऑक्शन के माध्यम से बंदोबस्त कर दिया गया। झारखंड सरकार ने आज तक बंदोबस्ती की दिशा में कदम भी नहीं उठाया। खदानों में खनन करके जो लौह अयस्क पड़ा हुआ है, उस लौह अयस्क को बेचने के बारे में भी कोई कदम नहीं उठाया है। अगर लौह-अयस्क को बेचा जाए तो करीब 300 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। उन्होंने विधानसभा में कई सवाल उठाए कि सरकार लौह-अयस्क को क्यों नहीं बेचती। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के सेंक्चुरी घोषित करने पर सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में सरकार है हाय-तौबा मचा रही है। आज भी सरकार अगर चाहती है कि सारंडा में सस्टेनेबुल माइनिंग हो तो जो इसके बारे में माइनिंग प्लान बनानेवालों ने अनुशंसा की है, उस पर सरकार अध्ययन करे और स्पष्ट रुख अख्तियार करे। ■

पारिस्थितिकी की नई सुबह

धरती को नया जीवन चाहिए

धरती केवल ग्रह नहीं, एक जीवित सत्ता है—उसकी नाड़ियों में जल बहता है, उसकी त्वचा पर वन उगते हैं, उसकी आँखों में नदियाँ चमकती हैं और उसकी सांस में वायु गूंजती है। इसी सजीव तंत्र को विज्ञान की भाषा में पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी केवल विज्ञान नहीं, एक जीवंत दर्शन है।

धरती बोल रही है। पर क्या हम सुन पा रहे हैं? धरती मौन नहीं है, वह बोलती हैः कभी वृक्षों की पत्तियों में, कभी नदियों की धाराओं में, कभी बादलों की गरज में, और कभी किसी घायल पक्षी की आँखों में। पर अब उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। हमने उसके हृदय पर विकास की तलवार चलाई है—और वह कराहते हुए भी हमें आशीर्वाद देती रही। अब जब उसके पर्वत धसक रहे हैं, नदियाँ थम रही हैं, वायु की साँसें भारी हो चली हैं, तो समय आ गया है कि मनुष्य ठहरकर यह पूछे—क्या हमने अपने अस्तित्व का आधार ही नहीं काट डाला? इसी आत्ममंथन के लिए ही 1 नवम्बर को विश्व पारिस्थितिकी दिवस मनाया जाता है—एक ऐसा दिवस, जो हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी कोई संपत्ति नहीं, वह चेतना है, मनुष्य उसका संरक्षक नहीं, उसका अंश है। धरती हमसे कुछ नहीं माँगती—बस यह चाहती है कि हम उसे जीने दें।

पारिस्थितिकी क्या है और यह दिवस क्यों महत्त्वपूर्ण है?

धरती केवल ग्रह नहीं, एक जीवित सत्ता है—उसकी नाड़ियों में जल बहता है, उसकी त्वचा पर वन उगते हैं, उसकी आँखों में नदियाँ चमकती हैं और उसकी सांस में वायु गूंजती है। इसी सजीव तंत्र को विज्ञान की भाषा में

पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी केवल विज्ञान नहीं, एक जीवंत दर्शन है। यह वह शास्त्र है जो बताता है कि जीवन की हर इकाई किसी अन्य के अस्तित्व से कैसे जुड़ी है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, प्राणवायु हैं; नदियां केवल जल नहीं, प्रवाह हैं; और पशु केवल प्राणी नहीं, संतुलन के प्रहरी हैं। पारिस्थितिकी का अर्थ है—जीव और उसके परिवेश के बीच संतुलित संबंध। यह वह सूक्ष्म रचना है जिसमें वृक्ष, जल, पशु, पक्षी, कीट, मिट्टी, आकाश और मनुष्य—सब एक ही सूत्र में बँधे हैं। यह संतुलन जब टूटता है, तब सृष्टि का संगीत बेसुरा हो जाता है।

पारिस्थितिकी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है—'ओइकोस' अर्थात् घर और 'लोगोस' अर्थात् विज्ञान या अध्ययन। अर्थात् यह अपने 'घर' अर्थात् पृथ्वी के अध्ययन का विज्ञान है। हर वर्ष 1 नवम्बर को विश्व पारिस्थितिकी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि मानवता यह याद रख सके कि यह ग्रह किसी एक जाति, धर्म, या संस्कृति की संपत्ति नहीं, बल्कि सबके लिए समान जीवनभूमि है। यह दिवस प्रकृति और मानव के बीच उस भूले हुए संवाद को पुनर्जीवित करने का आह्वान है, जो सभ्यता की भीड़ में कहीं खो गया। मानवता यह स्मरण कर सके कि पृथ्वी केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की जननी है। यह दिन हमें उस अदृश्य डोर का अनुभव कराता है, जो हर प्राणी को हर कण से जोड़ती है। पारिस्थितिकी वह सूत्र है जो सृष्टि को बाँधता है और उसका टूटना, अस्तित्व का विघटन है। पारिस्थितिकी वह धर्म है, जो हमें सिखाता है कि अस्तित्व का कोई भाग अनावश्यक नहीं होता।

भारत की पारिस्थितिकी की वर्तमान स्थिति: हरियाली का शोकगीत

भारत, जो कभी विश्व के जैव-विविधता के नखलिस्तान के रूप में प्रतिष्ठित था, अब पर्यावरणीय असंतुलन की भयावहता से जूझ रहा है। कभी वनों, नदियों और पर्वतों का महागीत था, आज विकास के शोर में अपनी हरियाली की करुणा खो चुका है।

तथ्य जो सोचने पर विवश करते हैं : कभी नदियाँ आशीर्वाद थीं, अब वे अपशिष्ट की धाराएँ बन गई हैं। वन सर्वेक्षण संस्थान और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, भारत का लगभग 30 प्रतिशत प्राकृतिक वन क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में लुप्त या कमजोर हुआ। 25 प्रतिशत वनस्पतियाँ और 20 प्रतिशत जीव प्रजातियाँ संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। केवल 5 प्रतिशत भूभाग प्रभावी रूप से संरक्षित है। देश के 60 प्रतिशत तटीय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से दूषित हैं। महानगरों की वायु गुणवत्ता विश्व में सबसे नीचे की श्रेणी में है। प्रमुख नदियों में घुलित ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से घटा है।

कारणों की परतें : अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, शहरी विस्तार, रासायनिक कृषि, खनन, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इन सबने धरती की साँसों पर बोझ बढ़ा दिया है। कभी भारत का गाँव जीवन का प्रतीक था; अब वही गाँव कारखानों की राख में छप से गये हैं। नदियाँ अब प्रवाह नहीं, विषधाराएँ बन चुकी हैं। वन केवल नक्शों में बचे हैं, खेतों की मिट्टी रासायनिक मृत्यु की ओर अग्रसर है। हमने जंगलों को कारखाने में बदला, फिर आश्चर्य किया कि वर्षा क्यों रूठ गई। धरती की थकान उसकी चुप्पी में

धरती का दस्तावेज़ : आँकड़ों में दर्ज सृष्टि की पीड़ा

भारत एवं विश्व की पारिस्थितिकी से जुड़े तथ्य (2025 तक)

वैश्विक तापमान वृद्धि: पिछले 150 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.3°C बढ़ा।

वन क्षेत्र ह्रास: विश्व में हर वर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि समाप्त होती है।

मानव प्रभाव: पृथ्वी की कुल भूमि का 75% भाग अब मानवीय क्रियाओं से प्रभावित है।

भारत का वन क्षेत्र: कुल भूभाग का केवल 21.67% भाग वनाच्छादित है (एफएसआई, 2023)।

वन ह्रास दर: 1990 से अब तक भारत के प्राकृतिक वनों में 30 % की गिरावट।

जैव विविधता संकट: भारत की 25% प्रजातियाँ संकटग्रस्त, 85 अत्यंत संकटग्रस्त (आईयूसीएन, 2024)।

तटीय प्रदूषण: भारत के 60% तटीय क्षेत्र दूषित (सीपीसीबी, 2023)।

वायु प्रदूषण: दिल्ली, पटना, कानपुर, लखनऊ विश्व के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में (डब्लूएचओ, 2024)।

ग्रीन ज़ोन अनुपात: प्रति व्यक्ति औसत हरित क्षेत्र 2.3 वर्गमीटर, जबकि डब्ल्यूएचओ (मानक 9 वर्गमीटर)

गिद्धों की जनसंख्या: 1990 में लगभग 4 करोड़, अब घटकर 1 लाख से भी कम। 97% की गिरावट।

हाथियों की संख्या: 1992 में 3 लाख, अब लगभग 30000।

चील–उल्लू प्रजातियाँ: पिछले दो दशकों में 40% तक कमी।

बाघों की संख्या: भारत में कुल 3167 (2022 की गणना अनुसार)।

प्रदूषित नदियाँ: भारत की 70% नदियाँ प्रदूषित, जल-गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर (सीपीसीबी, 2024)।

भूजल विषाक्तता: देश के 90% भूजल स्त्रोतों में भारी धातुएँ मानक से अधिक।

प्लास्टिक कचरा: प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन टन, जिसमें से केवल 9% पुनर्चक्रित।

वायु गुणवत्ता: महानगरों में औसत 350-450 (गंभीर श्रेणी)।

चरम मौसमी घटनाएँ: पिछले दशक में भारत में 3 गुना वृद्धि।

मानसून अनियमितता: वर्ष 2024 में वर्षा पैटर्न 15% विचलित।

हिमालयी ग्लेशियर: प्रतिवर्ष औसतन 0.3 मीटर पिघलाव।

कृषि संकट: भारत का 45% कृषि क्षेत्र अब जलवायु-संवेदनशील श्रेणी में।

वन ऊर्जा क्षमता: भारत के वनों की उत्पादक क्षमता में 15% गिरावट (नेचर सस्टेनेबिलिटी, 2024)।

प्रजाति संकट: 418 संकटग्रस्त, 85 अत्यंत संकटग्रस्त (आईयूसीएन, 2025)।

गिद्ध विलुप्ति प्रभाव: संक्रमणजन्य रोगों में 40% वृद्धि, आर्थिक क्षति 30अरब रुपये।

तापमान वृद्धि (भारत): 75% जिलों में तापमान औसतन 2.1°C अधिक (इंडियन क्लाइमेट इंडेक्स, 2025)।

अनुमान: 2050 तक भारत का 30% कृषि उत्पादन घट सकता है।

झलकती है—पर मनुष्य अपने शोर में इतना उलझ गया है कि सुन नहीं पाता।

जीव-जगत और पारिस्थितिकी का परस्पर संबंध, जो अब टूटने लगा हैः प्रकृति का हर जीव किसी उद्देश्य से जन्म लेता है, कोई भी जीव अकेला नहीं जीता। हर प्राणी किसी न किसी रूप में दूसरे के जीवन का कारण हैः पक्षी बीज फैलाते हैं, मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, गिद्ध शव नष्ट करते हैं, हाथी वन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह संतुलन ही जीवन का रहस्य है। नतीजा यह है कि जहाँ कभी गिलहरियाँ दौड़ती थीं, वहां अब सीमेंट है; जहाँ तितलियाँ उड़ती थीं, वहाँ धुआँ है; जहाँ गिद्ध आसमान में मंडराते थे, वहाँ अब मौन है। आज यह सहजीवन एकतरफा हो गया है। मनुष्य ले तो रहा है, पर लौटा कुछ नहीं रहा। उसने प्रकृति को साधन बना दिया और यही उसके पतन का आरंभ है। जब तक ये सब अपने कार्य कर रहे थे, धरती का संतुलन अक्षुण्ण था। अब यह चक्र टूट चुका है। मनुष्य ने प्रकृति को सहयोगी से शिकार बना दिया। फसलें अधिक उपजाने की लालसा में कीटनाशक बढ़े, जिन्होंने पक्षियों और कीटों की पीढ़ियाँ मिटा दीं। जलाशयों में विषैले अपशिष्टों ने मछलियों के समूह नष्ट किए। वनों की कटाई ने न केवल पेड़ों को, बल्कि पक्षियों के घरों को भी समाप्त कर दिया। मनुष्य ने जब प्रकृति से लेना सीखा, तब तक वह ईश्वर था; पर जब वह लौटाना भूल गया, तब वह विनाशक बन गया। प्रकृति से अलग हुआ मनुष्य, स्वयं से भी अलग हो गया।

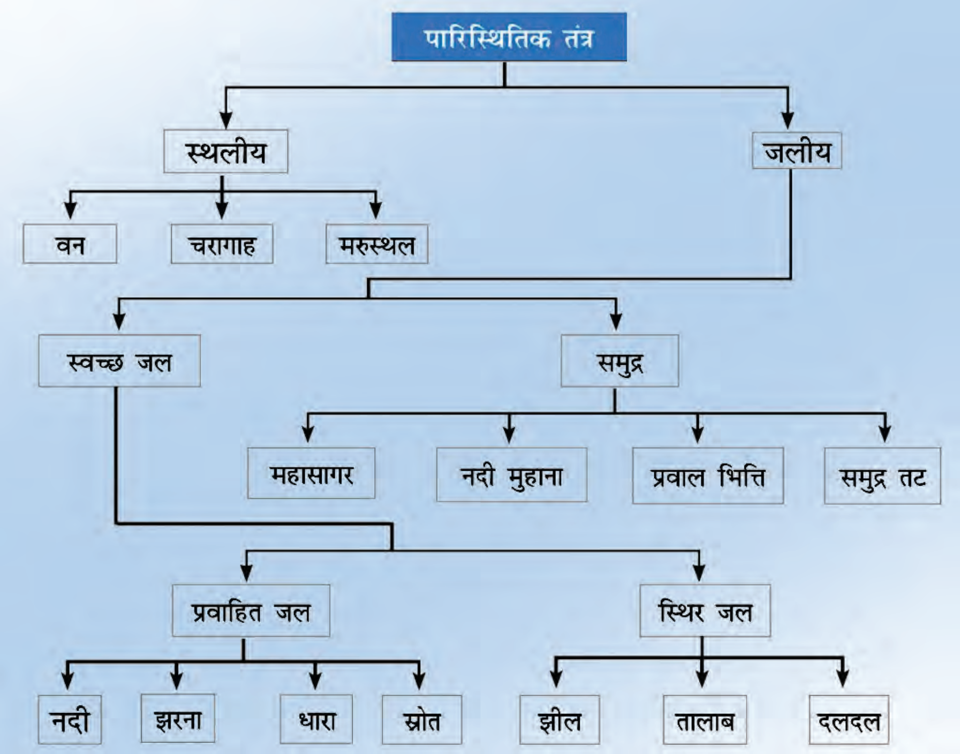

पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के उपायः विज्ञान और संवेदना का संगम

धरती अब 'सुधार' नहीं, पुनर्जन्म चाहती है। वह चाहती है कि मनुष्य केवल नीति नहीं, अपना जीवन-दर्शन बदले। वर्तमान समय नीति और निष्ठा के मेल से पुनर्निर्माण का है।

वनों का पुनर्जीवनःप्रत्येक वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देता, वह तापमान नियंत्रित करता है, वर्षा बुलाता है, जल को रोकता है। हर वृक्ष पृथ्वी का फेफड़ा है। वनों की रक्षा के बिना जलचक्र, वायुमंडल और तापमान का संतुलन असंभव है। नदियों की सफाई केवल योजना नहीं, श्रद्धा बननी चाहिए। वनों की रक्षा केवल वन विभाग का कार्य नहीं, यह राष्ट्र का दायित्व है।

जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि : रासायनिक विष मिट्टी की आत्मा को निगल चुका है। जैविक खेती मिट्टी, जल और मानव स्वास्थ्य तीनों को पुनर्जीवित कर सकती है। एक हेक्टेयर भूमि पर रासायनिक उर्वरकों के कारण हर वर्ष औसतन 2.5 टन सूक्ष्मजीव मर जाते हैं।

जल-स्रोतों का पुनरुद्धार : नदियों और तालाबों की सफाई के बिना कोई पारिस्थितिकी संभव नहीं। गंगा, गोमती, सरयू जैसी नदियों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अब उस सीमा से नीचे है, जहाँ मछलियाँ जीवित रह सकें।

वन्यजीव गलियारे और संरक्षण क्षेत्रः हाथियों, बाघों, भालुओं के प्रवास मार्गों की पुनर्स्थापना अत्यावश्यक है। रेखीय परियोजनाओं-जैसे रेल, सड़क, खनन में पारिस्थितिक योजना अनिवार्य की जाए। हाथियों और बाघों के प्रवास मार्ग सुरक्षित किए जाएँ। वन-परिदृश्य एकीकृत योजना के अंतर्गत आएँ, ताकि जीव स्वतंत्र विचरण कर सकें और मानव–वन्यजीव संघर्ष घटें।

जनभागीदारी और पर्यावरण शिक्षाः विद्यालयों में 'प्रकृति पाठ' अनिवार्य हो। बच्चे यह सीखें कि एक पेड़ गिरने से केवल छाया नहीं जाती बल्कि एक जीवन घटता है। कम लो, कम फेंको, अधिक बचाओ—यही जीवन-दर्शन बने। धरती की चिकित्सा केवल पौधे लगाना नहीं, अपनी आदतें बदलना है।

हाथी, चील और गिद्ध—धरती की करुण चेतावनी

हाथी, चील और गिद्ध हैं धरती के मौन प्रहरी। धरती ने जब भी संकट सहा, इन तीनों जीवों ने पहले संकेत दिया, पर हमने उनकी भाषा नहीं समझी। हाथी जंगलों का स्थापत्यकार है। हाथी जहाँ चलता है, वहाँ जीवन अंकुरित होता है।

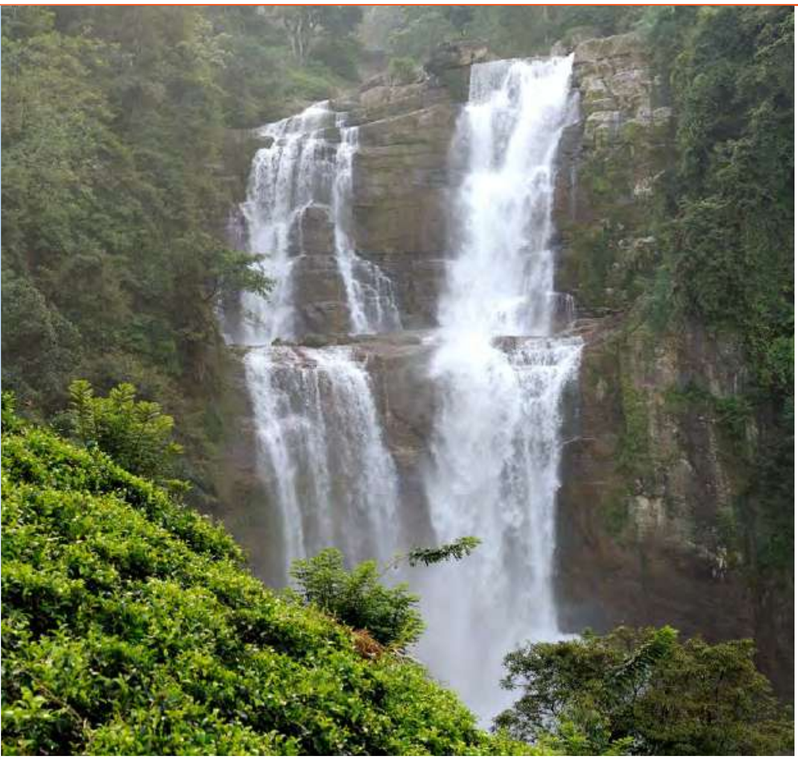

वह बीजों को फैलाता है, जल स्रोतों को खोजता है, वन का पारिस्थितिक अभियंता है। रेलमार्ग, सड़कों और शहरी विस्तार ने उसके रास्ते रोक दिए हैं। पिछले छह दशकों में उसकी संख्या 70 प्रतिशत तक घट चुकी है। हाथी का लोप जंगलों की आत्मा के पतन का संकेत है। उनका लोप केवल एक प्रजाति का नहीं, पूरे वन-तंत्र का पतन है।

चील : वायु प्रहरी

चीलें वायु-मंडल की प्रहरी और आकाश की आँखें थीं। उनकी अनुपस्थिति बताती है कि वायु और आकाश दोनों दूषित हैं। वायुमंडल का यह मौन धरती की बढ़ती थकान का संकेत है। उनका पतन वायु-मंडल की बीमारियों का प्रारंभिक संकेत है।

गिद्ध : स्वच्छता का मूक देवदूत

गिद्ध, जो मृत शरीरों को समाप्त कर रोगों को रोकते थे, प्रकृति की सफाई प्रणाली थे। अब लगभग लुप्त हो गए हैं। 'डाइक्लोफेनाक' नामक पशु-दवा ने उनकी प्रजातियों का सफाया कर दिया। गिद्धों की अनुपस्थिति से संक्रमण, जल-प्रदूषण और बीमारियाँ बढ़ीं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, उनके लोप से देश को 30 अरब रुपये से अधिक आर्थिक क्षति हुई है और लाखों अप्रत्यक्ष मौतों का सामना करना पड़ा। उनकी जनसंख्या में 90% से अधिक गिरावट हुई है। अब खुले शव, सड़ांध और संक्रमण सब उनकी अनुपस्थिति का मौन प्रमाण हैं। जब गिद्ध नहीं दिखते, तब धरती की सभ्यता सड़ने लगती है और आकाश श्मशान बन जाता है। ये तीनों जीव बताते हैं कि जब प्रहरी मौन हो जाते हैं, तो धरती बोलती नहीं, कराहती है।

शोध और वैज्ञानिक निष्कर्ष: पृथ्वी की निदान रिपोर्ट

विज्ञान और संवेदना दोनों आज एक ही बात कह रहे हैं-धरती बीमार है। नेचर सस्टेनेबिलिटी (2024) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, भारत के जंगलों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 15 प्रतिशत तक घटी है। प्राणी सर्वेक्षण विभाग (2025) के अनुसार भारत की 418 प्रजातियाँ संकटग्रस्त, 85 अत्यंत संकटग्रस्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत की पाँच प्रमुख नदियों का जल मानव-उपयोग योग्य नहीं रहा। भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का 60 प्रतिशत भाग औद्योगिक गतिविधियों से दूषित है। गिद्धों के पतन से संक्रमणजन्य रोगों में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। हाथियों की घटती संख्या के कारण 20 प्रतिशत वनों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन दर घट गई। ये सारे तथ्य एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं—धरती की नाड़ियाँ कमजोर हैं, उसकी धड़कन धीमी पड़ रही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि देश के 60% तटीय क्षेत्र प्रदूषण और मानव अतिक्रमण से नष्ट हो चुके हैं। गिद्धों के पतन से संक्रमणजन्य रोगों में 40% वृद्धि दर्ज की गई। ये सभी शोध एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं—धरती की नाड़ियों में अब वह रक्तसंचार नहीं रहा, जो कभी उसे जीवंत बनाता था। विज्ञान चेतावनी दे रहा है, संवेदना शोकगीत गा रही है। धरती का रोगी स्वयं मनुष्य है, चिकित्सक भी वही है। धरती को केवल बचाना नहीं, उससे फिर से प्रेम करना होगा। धरती को न उपासना चाहिए, न उपभोग-बस सहयोग चाहिए। वह कहती है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ जीओ, मेरे साथ साँस लो। धरती चाहती है कि हम उसके साथ फिर से संवाद करें। जब मनुष्य फिर से वृक्षों की भाषा समझेगा, नदियों की लय पहचानेगा,

पक्षियों की पुकार सुनेगा—तभी वह स्वयं को पहचान पाएगा। हमारे निर्णय—घर बनाना, भोजन चुनना, यात्रा करना—सबका असर पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए अब हर मनुष्य को अपनी जीवनशैली में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व जोड़ना होगा। जब अंतिम वृक्ष गिर जाएगा, अंतिम नदी जब सूख जाएगी, अंतिम पक्षी उड़ना बंद कर देगा, तब मनुष्य को समझ में आएगा कि धन खाया नहीं जा सकता। धरती हमारी जननी है। उसका आकाश हमारा छत है, उसकी मिट्टी हमारी देह है, उसका जल हमारी सांस है। यदि हमने इसे खो दिया, तो न धर्म बचेगा, न विज्ञान, न संगीत—बस शेष रह जाएगी तो सिर्फ शून्यता...। धरती की रक्षा किसी नीति की जिम्मेदारी नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जब मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के आगे विनम्रता सीखेगा, तभी पृथ्वी फिर से हरी होगी। ■

ग्रीनहाउस गैसों ने तोड़े रिकॉर्ड
मीथेन में 166 फीसदी की वृद्धि

वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा ही कुछ 2024 में भी दर्ज किया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का वार्षिक औसत स्तर बढ़कर 423.9 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गया।

▪ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

इस बारे में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अपनी नई रिपोर्ट में पुष्टि की है कि 2024 में वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का स्तर रिकॉर्ड उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंच गया, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का होना करीब-करीब तय हो गया है। डब्ल्यूएमओ ने रिपोर्ट में जानकारी दी है कि 1960 के दशक से सीओ2 में हो रही वृद्धि की दर तीन गुणा बढ़ गई है। 2011 से 2020 के बीच में यह दर सालाना 0.8 पीपीएम से बढ़कर 2.4 पीपीएम हो गई। वहीं 2023 से 2024 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक औसत स्तर में 3.5 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) की दर से वृद्धि हुई है, जो 1957 में आधुनिक माप शुरू होने के बाद से इसमें दर्ज सबसे बड़ा वार्षिक उछाल है।

सीओ2 के स्तर में आया 12.4 फीसदी का उछाल

गौरतलब है कि जब 2004 में यह बुलेटिन पहली बार प्रकाशित हुआ था, तब डब्ल्यूएमओ के ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच नेटवर्क की माप के अनुसार सीओ2 का वार्षिक औसत स्तर 377.1 पीपीएम था। 2024 में बढ़कर 423.9 पीपीएम पर पहुंच गया है।

मतलब की इसमें पिछले दो दशकों में 12.4 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि 2023 में यह स्तर 420 भाग प्रति मिलियन

(पीपीएम) रिकॉर्ड किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के नवीनतम अंक के मुताबिक इसके लिए हम इंसान जिम्मेवार हैं। इंसानी गतिविधियों के साथ-साथ धधकते जंगलों की वजह से हो रहा उत्सर्जन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के तेजी से बढ़ते स्तर के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। साथ ही, भूमि और महासागर जैसे कार्बन "सिंक्स" की सीओ2 को अवशोषण करने की क्षमता में आती गिरावट भी स्थिति को और गंभीर बना रही है।

वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इससे एक खतरनाक जलवायु चक्र बन सकता है, जिससे जलवायु संकट और गंभीर रूप ले सकता है। डब्ल्यूएमओ की उप महासचिव को बैरेट ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "सीओ2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसें हमारी जलवायु को तेजी से बदल रही हैं और चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा रही हैं। ऐसे में बढ़ते उत्सर्जन को कम करना सिर्फ जलवायु के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए भी बेहद जरूरी है।"

चिंता की बात यह है कि हर साल उत्सर्जित होने वाले कुल सीओ2 का करीब आधा वातावरण में ही बना रहता है, जबकि बाकी भूमि और महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हालांकि इनका संग्रह स्थाई नहीं है। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता घट रही है, क्योंकि बढ़ते तापमान में सीओ2 का पानी में घुलना कम हो जाता है।

इसी तरह पेड़-पौधे और भूमि पर मौजूद अन्य कार्बन सिंक्स भी कई तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा जैसी घटनाएं शामिल हैं।

रिपोर्ट में 2023 से 2024 के बीच सीओ2 में हुई रिकॉर्ड वृद्धि के लिए जंगलो में धधकती आग की वजह से बढ़ते उत्सर्जन और भूमि व महासागरों द्वारा सीओ2 के कम अवशोषण को माना गया है। गौरतलब है कि 2024 जलवायु इतिहास का अब तक का सबसे गर्म वर्ष था और इसमें मजबूत अल नीनो की घटना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।अल नीनो वर्षों में सीओ2 का स्तर बढ़ने का कारण यह है कि सूखी वनस्पति और जंगल की आग के कारण भूमि के कार्बन सिंक्स कम प्रभावी हो जाते हैं। 2024 में अमेजन और दक्षिण अफ्रीका में असाधारण सूखा और जंगल की आग भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे।

डब्ल्यूएमओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक ऑक्साना तारासोवा का कहना है, "भूमि और महासागर के सीओ2 सिंक्स कम प्रभावी होते जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर तापमान और बढ़ जाएगा। इस चक्र को समझने के लिए ग्रीनहाउस गैस की लगातार और मजबूत निगरानी जरूरी है।"

रिपोर्ट में इस बात को लेकर भी चेताया है कि आज वातावरण में उत्सर्जित सीओ2 न केवल मौजूदा जलवायु को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके लम्बे समय तक वातावरण में बने रहने के कारण यह सैकड़ों सालों तक पृथ्वी की जलवायु पर असर डालता रहेगा।

मीथेन में 166 फीसदी की वृद्धि दर्ज

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो मानव गतिविधियों से जुड़े दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस हैं, वे भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर मीथेन का औसत स्तर

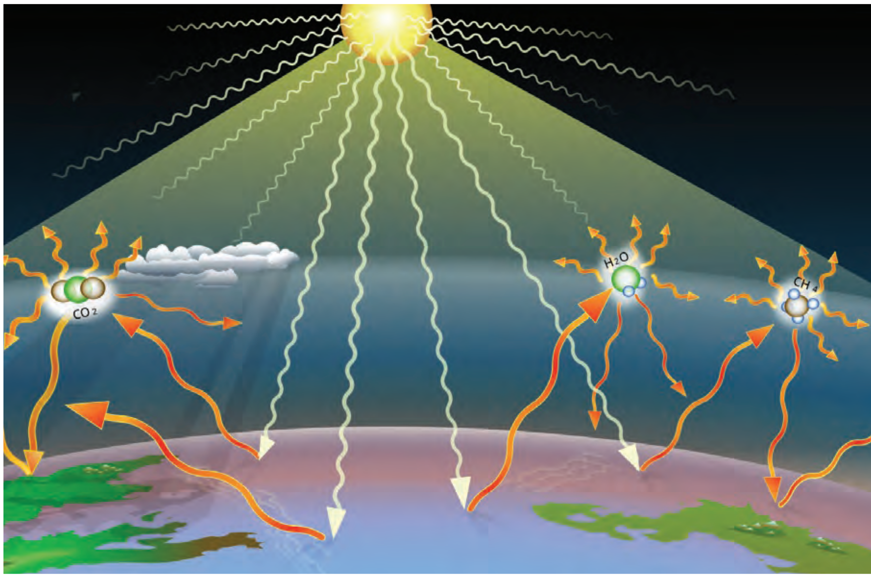

1942 भाग प्रति बिलियन (पीपीबी) रिकॉर्ड किया गया, जो औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 166 फीसदी अधिक है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड भी 25 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 338 पीपीबी तक पहुंच गया है। मीथेन वातावरण में करीब नौ वर्षों तक बनी रहती है। यह पृथ्वी की बढ़ती गर्मी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लंबी आयु वाली ग्रीनहाउस गैसों में करीब 16 फीसदी गर्मी पैदा करने वाले प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि करीब 40 फीसदी मीथेन प्राकृतिक स्रोतों, जैसे दलदली क्षेत्र, से वातावरण में उत्सर्जित हो रही है, जो खुद भी जलवायु के प्रति संवेदनशील हैं। बाकी करीब 60 फीसदी मीथेन इंसानी स्रोतों से आ रही है, जिनमें पशुपालन, धान की खेती, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, कचरा और बायोमास जलाना जैसे कारण जिम्मेवार हैं। ■

मीथेन वातावरण में करीब नौ वर्षों तक बनी रहती है। यह पृथ्वी की बढ़ती गर्मी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लंबी आयु वाली ग्रीनहाउस गैसों में करीब 16 फीसदी गर्मी पैदा करने वाले प्रभाव के लिए जिम्मेदार है।

अस्थमा वाला इनहेलर पर्यावरण के लिए खतरा

मीटर्ड-डोज इनहेलर (एमडीआई) से हुआ 98 फीसदी कार्बन उत्सर्जन, जो हर साल 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। ड्राई पाउडर और सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्प हैं क्योंकि इनमें प्रोपेलेंट गैस का उपयोग नहीं होता। शोध में सामने आया कि इनहेलर का उत्सर्जन 5.3 लाख पेट्रोल कारों के बराबर प्रदूषण करता है।

▪ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

अस्थमा और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के इलाज में इनहेलर एक जरूरी दवा संबंधी उपकरण बन चुके हैं। एक नई अमेरिकी अध्ययन के अनुसार, ये इनहेलर न सिर्फ सांस की बीमारियों से लड़ने में मदद कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स द्वारा किए गए इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में इनहेलर के उपयोग से हर साल 20 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुआ है। यह उत्सर्जन लगभग 5.3 लाख पेट्रोल-चालित कारों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है।

शोध के मुख्य निष्कर्ष: सबसे अधिक नुकसानदायक हैं मीटर्ड-डोज इनहेलर, इस अध्ययन में अमेरिका में 2014 से 2024 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें तीन प्रकार के इनहेलर शामिल थेः मीटर्ड-डोज इनहेलर (एमडीआई), ड्राई पाउडर इनहेलर

इनहेलर अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हीं मरीजों की स्थिति और बिगड़ सकती है जो पहले से ही सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। जामा नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।

(डीपीआई) और सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुल उत्सर्जन का 98 फीसदी केवल मीटर्ड-डोज इनहेलर से आया। इसका कारण है इनमें प्रयुक्त हाइड्रोफ्लोरोएल्केन (एचएफए) प्रोपेलेंट, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। पहले यह स्प्रे और एरोसोल उत्पादों में भी उपयोग होती थी, लेकिन अब इसकी जगह अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की सिफारिश की जाती है। इसके विपरीत, ड्राई पाउडर इनहेलर और सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर बिना प्रोपेलेंट के दवा प्रदान करते हैं, जिससे उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया कि इनहेलर अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हीं मरीजों की स्थिति और बिगड़ सकती है जो पहले से ही सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। जामा नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।

शोधकर्ताओं ने अमेरिका के एक नेशनल ड्रग कोड (एनडीसी) स्तर के व्यापक डाटाबेस का उपयोग करके विभिन्न ब्रांड, दवा प्रकारों, इनहेलर डिजाइनों, प्रोपेलेंट की मात्रा, बीमा प्रदाताओं और फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर की भूमिका का विश्लेषण किया। शोध में कहा गया कि अब शोधकर्ता आगे दवा लेने वाली जैसी विशेष आबादी में इनहेलर के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने जा रही है। इसके अलावा वे यह भी अध्ययन करेंगे कि क्या कम-उत्सर्जन इनहेलर उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पारंपरिक इनहेलर। साथ ही, दवा कंपनियों की कीमत निर्धारण और पेटेंट रणनीतियों का विश्लेषण भी किया जाएगा। इस अध्ययन के प्रकाश में आने के बाद अब डॉक्टरों, मरीजों और नीति-निर्माताओं के पास एक अवसर है कि वे स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सतत बना सकें। कुछ सुझाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- चिकित्सकों को चाहिए कि जब भी संभव हो, वे ड्राई पाउडर या सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर को प्राथमिकता दें।
- स्वास्थ्य नीति निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों पर आधारित इनहेलर के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
- जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि मरीज भी अपने डॉक्टर से पर्यावरण-मित्र विकल्पों के बारे में पूछ सकें।
- दवा कंपनियों को चाहिए कि वे कम उत्सर्जन वाले विकल्पों को सुलभ और किफायती बनाएं।

इस अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि यदि हम पर्यावरणीय प्रभावों को अनदेखा करते रहेंगे, तो यह न केवल धरती के लिए नुकसानदायक होगा, बल्कि स्वयं रोगियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। शोध में कहा गया है कि बदलाव की दिशा में पहला कदम है समस्या के पैमाने को समझना। उसके बाद हम लक्षित रणनीतियां बना सकते हैं जो मरीजों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हों। ■

इजरायल और हमास के बीच दो साल तक चले संघर्ष के बाद अब बेशक गाजापट्टी में गोलियां नहीं चल रही हैं, लोग धीरे-धीरे रुटीन लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहे हैं पर इन दो सालों में गाजा में जो घातक हथियार इस्तेमाल हुए, उन्होंने बड़ा लंबा नुकसान किया है प्रकृति का। 97 फीसदी पेड़ नष्ट हो गए हैं। 6.1 करोड़ टन मलबा जमा हो गया है....

इजरायल-हमास के दो साल चले संघर्ष में

गाजा के 97 फीसदी पेड़ नष्ट पर्यावरण की हुई है गंभीर क्षति

▪ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

गाजा में पांच लाख से अधिक लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और करीब 10 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। करीब ढाई लाख इमारतों में से 78 फीसदी क्षतिग्रस्त या पूरी तरह ढह गई हैं। इसकी वजह से करीब 6.1 करोड़ टन मलबा जमा हो गया है, जो आकार में मिस्र के 15 ग्रेट पिरामिड या 25 एफिल टावर जितना है। 97 फीसदी पेड़ नष्ट हो गये हैं।

आपको पता ही है कि युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते। इसमें कभी किसी की जीत नहीं होती, क्योंकि यह अपने पीछे तबाही के ऐसे निशान छोड़ जाते हैं, जिनको भरने में दशकों लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ गाजा में देखने को मिल रहा है, जहां मानवीय त्रासदी के साथ पर्यावरण को भी ऐसी घाव मिले, जिन्हें भरने में सदियां नहीं तो दशकों जरूर लग जाएंगे।

गाजा में हुई इस पर्यावरणीय त्रासदी की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट ने भी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में दो वर्षों से जारी संघर्ष ने पर्यावरण को अभूतपूर्व नुकसान

पहुंचाया है। इसमें मिट्टी, साफ पानी की आपूर्ति और समुद्र तट पर पड़ा गंभीर प्रभाव शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस नुकसान से उबरने को गाजा को दशकों का समय लगेगा।

रिपोर्ट के अनुसार गाजा में साफ पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। वहां पानी सीमित बचा है और जो है वो भी प्रदूषित है। पाइपलाइन और सीवेज प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से शौच के लिए गड्ढों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण भूजल की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ा है। गाजा की अधिकतर आबादी पानी के लिए भूजल पर ही निर्भर है। समुद्र और तटीय क्षेत्र के भी प्रदूषित होने की आशंका है, हालांकि वहां जांच अभी संभव नहीं है। इस जल संकट की वजह से वहां संक्रामक बीमारियां भी तेजी से पैर पसार रही हैं। स्थिति इस कदर खराब है कि वहां दस्त के गंभीर मामले 36 गुणा तक बढ़ गए हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस-ए से जुड़े पीलिया सिंड्रोम के मामलों में 384 गुणा वृद्धि हुई है। पेड़-पौधे, हरियाली करीब-करीब खत्म हो गई है।

आंकड़ों के मुताबिक 2023 से अब तक वहां 97 फीसदी पेड़, 95 फीसदी झाड़ियां और 82 फीसदी मौसमी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन अब असंभव हो गया है। इस बीच गाजा में पांच लाख से अधिक लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और करीब 10 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं।

संघर्ष से गाजा में मिट्टी की प्राकृतिक संरचना पर भी असर पड़ा है। इससे पानी के अवशोषण की क्षमता घट गई है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और भूजल का पुनर्भरण कम हुआ है।

गाजा में हुई इस पर्यावरणीय त्रासदी की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट ने भी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में दो वर्षों से जारी संघर्ष ने पर्यावरण को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है।

रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि जून 2024 में किए पिछले आकलन की तुलना में अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए, अब मलबे की मात्रा 57 फीसदी बढ़ गई है और यह 2008 के बाद गाजा में हुए सभी संघर्षों से पैदा हुए मलबे की तुलना में 20 गुणा अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में गाजा के पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए 30 सिफारिशें भी दी हैं। इनमें पानी और सीवेज ढांचे का तेजी से पुनर्निर्माण, मिट्टी की व्यवस्थित जांच, मलबे को हटाना व जहां संभव हो उसका पुनर्चक्रण, और हथियारों के अवशेषों का सुरक्षित निपटान करना शामिल है।

आकलन के अनुसार, गाजा का पर्यावरण तभी सुधर सकता है जब सावधानीपूर्वक, समावेशी और वैज्ञानिक योजना पर काम किया जाए। यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन का प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। अगर यह जारी रहा तो यह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा असर छोड़ेगा। गाजा में फैले मानवीय संकट को खत्म करना सबसे पहली प्राथमिकता है। जीवन बचाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था बहाल करना और मलबा को हटाकर मानवीय राहत पहुंचाना और जरूरी सेवाएं चालू करना बेहद जरूरी है। साथ ही, मिट्टी, जलस्रोतों और हरियाली को पुनर्जीवित करना गाजा के लोगों की खाद्य और जल सुरक्षा तथा उनके बेहतर भविष्य के लिए अहम होगा। ■

पलामू में अवैध खनन पर एनजीटी खफा

एनजीटी ने निर्देश दिया है कि अवैध खनन से संबंधित कितने मामलों में जांच जारी है, इसमें कितना समय लगेगा, और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।

▪ सुसान चाको

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड के पलामू जिले में अवैध पत्थर खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने पुलिस अधीक्षक से अप्रैल 2024 से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है, जिसमें दर्ज एफआईआर, जब्त वाहन, गिरफ्तारियां और दायर चार्जशीट शामिल हैं। अवैध खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी गई है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 अक्टूबर 2025 को झारखंड के पलामू जिले में अवैध पत्थर खनन रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

एनजीटी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे अप्रैल 2024 से अब तक दर्ज की गई अवैध खनन से संबंधित शिकायतों की संख्या, दर्ज एफआईआर, जब्त किए गए वाहन और पत्थर, गिरफ्तारियां और रिकवरी, और दायर चार्जशीट की पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।

एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया है कि अवैध खनन से संबंधित कितने मामले जांच के तहत हैं, जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा, और अवैध खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए। इनमें कैमरे लगाना, चेकपोस्ट बनाना और जीपीएस वाले वाहनों के माध्यम से खनन सामग्री, जैसे पत्थर, के परिवहन की अनुमति शामिल है।

एनजीटी की पूर्वी पीठ ने पलामू के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने के लिए 2020 के सैंड माइनिंग एंफोर्समेंट और मॉनिटरिंग गाइडलाइंस के तहत उठाए गए प्रत्येक उपाय की जानकारी तालिका के रूप में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जिला टास्क फोर्स द्वारा मारे गए छापों का विवरण और अप्रैल 2024 से अब तक हुई टास्क फोर्स की बैठकों के मिनट्स भी प्रस्तुत किए जाएं।

इसके अलावा, जिला खनन अधिकारी को स्टोन क्रशर पर लगाए गए नियमों की जानकारी, खनन पट्टेदार से कच्चे माल की आपूर्ति का खुलासा, रिपोर्टिंग और विभाग द्वारा ऑडिट, उल्लंघनों और उनके खिलाफ कार्रवाई के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 अक्टूबर 2025 को तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो मध्य प्रदेश की कलियासोत नदी में बायोमेडिकल कचरा फेंके जाने की शिकायत की जांच करेगी। समिति मौके का दौरा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की जानकारी एनजीटी को सौंपेगी।

इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2025 को होगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 अक्टूबर 2025 को दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे रवीन्द्रनगर के मक्खालहाटी गांव स्थित जलस्रोत को अतिक्रमण और कचरे से मुक्त कराने की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें।

तथ्यों की जांच के लिए एनजीटी के आदेश पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह जलस्रोत 'पुकुर' (तालाब) के रूप में दर्ज है। समिति ने पाया कि तालाब जलकुंभी से ढका हुआ है और इसके आसपास कचरे का ढेर जमा है।

इससे पहले, 15 जनवरी 2025 को एनजीटी ने दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को एक महीने के भीतर तालाब से कचरा, जलकुंभी और अन्य पौधे हटाकर उसे उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दिया था।

लेकिन, अदालत को जानकारी दी गई है कि संबंधित अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 अक्टूबर 2025 को तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो मध्य प्रदेश की कलियासोत नदी में बायोमेडिकल कचरा फेंके जाने की शिकायत की जांच करेगी। समिति मौके का दौरा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की जानकारी एनजीटी को सौंपेगी।

इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पीठ में होगी।

यह मामला भोपाल स्थित एच के कालचुरी एजुकेशन ट्रस्ट (एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज और जे के हॉस्पिटल) द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय उल्लंघनों से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, ये संस्थान कलियासोत नदी में बिना रोक-टोक के बायोमेडिकल कचरा डाल रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने नदी के किनारे निर्धारित हरित पट्टी क्षेत्र में अवैध निर्माण करके पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का भी उल्लंघन किया है।

गौरतलब है कि कलियासोत, बेतवा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो अंततः गंगा नदी बेसिन में मिल जाती है। ■

खतरे में है लखनऊ का चांदे बाबा तालाब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे चांदे बाबा तालाब के संरक्षण और सुधार के लिए उठाए कदमों की जानकारी एक शपथपत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही तालाब का ड्रोन वीडियो भी अदालत में जमा करने का निर्देश एनजीटी ने दिया है।

■ **सुनयना चाको**

अक्टूबर 8, 2025 को अदालत ने कहा कि ड्रोन वीडियो तालाब की वर्तमान स्थिति का सही मूल्यांकन करने में मदद करेगी। साथ ही, यह दृश्य न केवल तालाब की मौजूदा दशा को दिखाएंगे साथ ही उसकी बहाली और संरक्षण कार्यों में भी सहायक होंगे।

इसमें जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी शामिल है। यह मामला लखनऊ के गांव गढ़ी-चुनौती में स्थित 'चांदे बाबा तालाब' के संरक्षण और विकास से जुड़ा है। सर्दियों में यह तालाब हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, लेकिन तालाब के आसपास अतिक्रमण और जलस्तर में गिरावट के कारण पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

तालाब का जल स्रोत 'नगवा नाला' नामक एक तूफानी जलनिकासी नाला है। यह नाला साई नदी में मिल जाता है और इसका ताजा पानी बेकार चला जाता है। आवेदक ने कहा है कि तालाब का जलस्तर बढ़ाने के लिए इस नाले को चांदे बाबा तालाब से जोड़ा जाना चाहिए।

अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, चांदे बाबा तालाब का कुल

क्षेत्रफल 36.909 हेक्टेयर है, जिसमें से 3.1859 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 8 मई 2023 को सबमिट रिपोर्ट में माना था कि आस-पास के क्षेत्रों से सीवेज ले जा रह एक नाले का दूषित पानी बिना किसी उपचार के चांदे बाबा तालाब में डाला जा रहा है।

एसपीसीबी की केंद्रीय प्रयोगशाला में नाले में छोड़े जा रहे सीवेज के नमूना का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से पता चला कि इस पानी में बीओडी, टोटल कॉलिफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज्यादा है, जबकि इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई। एनजीटी को सौंपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, "इलाके का दूषित सीवेज सीधे चांदे बाबा तालाब में मिल रहा है, जो तालाब में पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है।"

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच ने 7 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने मध्य प्रदेश के दतिया जिले के वन विभाग को निर्देश दिया गया है कि यदि साकी घाट, नदी महुआर के पास गांव घुघसी और ओरिना में कोई रेत या बजरी का खनन पाया जाता है तो उसे तुरंत रोका जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके लिए वन अधिनियम, 1980 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। एनजीटी में प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि बिना खनन लीज के रोजाना 150 से 200 ट्रैक्टर साकी घाट से बजरी लोड कर रहे हैं, जबकि यह क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साकी घाट में नदी महुआर के पास घुघसी और ओरिना में किसी प्रकार का बजरी या रेत खनन नहीं हो रहा है। खनन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में खनन के लिए कोई लीज जारी नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस स्थल पर रेत या बजरी जमा है वो पूरी तरह से वन भूमि में है और वहां वाहनों के पहुंचने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

संयुक्त समिति ने यह भी कहा है कि वन विभाग और खनन विभाग के पास अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पेट्रोलिंग और चेकपोस्ट का सिस्टम मौजूद है। रिपोर्ट में दोनों विभागों से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने और नदी घाटों तक जाने वाले रास्तों में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बाधाएं स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

तालाब का जल स्रोत 'नगवा नाला' नामक एक तूफानी जलनिकासी नाला है। यह नाला साई नदी में मिल जाता है और इसका ताजा पानी बेकार चला जाता है। आवेदक ने कहा है कि तालाब का जलस्तर बढ़ाने के लिए इस नाले को चांदे बाबा तालाब से जोड़ा जाना चाहिए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 8 अक्टूबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा है कि एनजीटी पर्यावरणीय मुआवजा कोष के तहत चल रहे 24 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक फंड उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सीपीसीबी ने एनजीटी से अनुरोध किया है कि वह इन 24 परियोजनाओं और एनजीटी के निर्देशानुसार अन्य गतिविधियों, अध्ययनों, परियोजनाओं या खर्चों के लिए एनजीटी के पर्यावरणीय मुआवजा कोष का उपयोग जारी रखने की अनुमति दें।

सीपीसीबी रिपोर्ट में एनजीटी फंड के अंतर्गत चल रही 24 परियोजनाओं की सूची भी दी गई है। इनमें महाराष्ट्र के साकरवाड़ी में गोदावरी बायोरिफाइनरीज के डिस्टिलरी स्पेंट वॉश के डि-स्लज और रिफिल किए गए लैगून की दूषित मिट्टी, सतही जल और भूजल का बायोरिमेडिएशन शामिल है। एक अन्य परियोजना पानीपत रिफाइनरी के आसपास पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भूजल के पुनरुद्धार की योजना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर उपग्रह आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी भी एनजीटी फंड के तहत शामिल परियोजनाओं में हैं। गौरतलब है कि एनजीटी ने 9 सितंबर 2025 को सीपीसीबी को यह बताने का निर्देश दिया था कि इन 24 परियोजनाओं में से किसी के लिए कोई वैकल्पिक फंडिंग स्रोत उपलब्ध है या नहीं। साथ ही, सीपीसीबी को सभी फंडिंग स्रोतों (अनुदान और अन्य स्रोत) और प्राप्त राशि का खुलासा करने के लिए भी कहा था।

सीपीसीबी रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पास पांच प्रकार के फंड उपलब्ध हैं, इनमें अनुदान 126 करोड़ रुपए, केंद्रीय योजनाएं 7.51 करोड़ रुपए, पर्यावरण संरक्षण शुल्क फंड 347.5 करोड़ रुपए, सीपीसीबी द्वारा स्वयं-सृजित फंड 98.35 करोड़ रुपए शामिल हैं। ■

• स्पेशल स्टोरी •

दलमा का दर्द
हाथी आबादी का संकट और संरक्षण की उम्मीद

■ एस. विद्यासागर

झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की संख्या घटकर महज 10 रह गई है। यह खबर न केवल स्थानीय निवासियों को चिंतित कर रही है, बल्कि वन्यजीव प्रेमियों के बीच एक बहस छेड़ रही है। क्या ये विशालकाय प्राणी मर रहे हैं, या फिर वे अपनी प्राचीन यात्राओं पर निकल पड़े हैं? दलमा कभी हाथियों का स्वर्ग माना जाता था। आज मानव हस्तक्षेप और पर्यावरणीय दबावों के कारण एक सवाल बन चुका है। बीते 30 वर्षों में यहां की हाथी आबादी में उतार-चढ़ाव ने एक रोचक कहानी बुनती है। कभी बेबी बूम की खुशी, तो कभी संघर्ष की उदासी।

दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जमशेदपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर 192 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। यहां साल, महुआ और बांस के घने जंगल हाथियों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। लेकिन 2025 के प्रारंभिक सर्वेक्षणों के अनुसार, अभयारण्य के कोर इलाके में केवल 10 हाथी बचे हैं, जबकि बाकी झुंड चाकुलिया और घाटशिला जैसे आसपास के क्षेत्रों में 40-45 हाथी भटक रहे हैं। यह संख्या 2022 के 105 हाथियों से बेहद कम है, जो चिंताजनक है। लेकिन क्या यह स्थायी क्षति का संकेत है? या हाथियों की प्रवासी प्रकृति का परिणाम? आइए, पहले समझते हैं कि इन विशाल जीवों की गिनती आखिर कैसे होती है।

हाथियों की गिनती: विज्ञान और धैर्य का मेल

भारत में हाथी गणना एक जटिल, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो हर पांच वर्ष में आयोजित की जाती है। इसे वन्यजीव संस्थान ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) देहरादून के नेतृत्व में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा संचालित किया जाता है। यह गणना न केवल संख्या बताती है, बल्कि आबादी की

सेहत, प्रवास पैटर्न और संघर्ष क्षेत्रों का भी आकलन करती है। प्रक्रिया कई चरणों में बंटी होती है, जो प्रत्यक्ष अवलोकन से लेकर आधुनिक तकनीक तक फैली है। सबसे पारंपरिक विधि है वाटरहोल सेंसस, जहां गर्मियों में हाथियों के पसंदीदा जलाशयों पर नजर रखी जाती है। दलमा जैसे क्षेत्रों में जहां गर्मी में हाथी झुंडबद्ध होकर पानी की तलाश में आते हैं, वन अधिकारी और स्वयंसेवक इन स्थानों पर तंबू गाड़कर रात-दिन निगरानी करते हैं। 2019 में दलमा में इसी विधि से 48 से बढ़कर 66 हाथी गिने गए थे। लेकिन यह विधि सीमित है, क्योंकि सभी हाथी एक साथ नहीं आते।

अधिक सटीकता के लिए सिंक्रोनाइज्ड एलीफैंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन अपनाई जाती है, जो पूरे देश में एक साथ चलती है ताकि डबल काउंटिंग न हो। इसमें लाइन ट्रांसेक्ट विधि शामिल है, जहां अधिकारी जंगल में 1-2 किलोमीटर लंबी लाइनों पर चलते हुए हाथियों के पदचिह्न, गोबर और टूटे पेड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। आधुनिक टच आता है डीएनए प्रोफाइलिंग से हाथियों के गोबर से डीएनए निकालकर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाती है। 2023 में भारत का पहला डीएनए-आधारित सेंसस इसी तकनीक पर आधारित था, जिसमें 1,500 से अधिक सैंपल एकत्र किए गए। इसके अलावा कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन सर्वे का उपयोग बढ़ रहा है।

तालाब का जल स्रोत 'नगवा नाला' नामक एक तूफानी जलनिकासी नाला है। यह नाला साई नदी में मिल जाता है और इसका ताजा पानी बेकार चला जाता है। आवेदक ने कहा है कि तालाब का जलस्तर बढ़ाने के लिए इस नाले को चांदे बाबा तालाब से जोड़ा जाना चाहिए।

दलमा में 2025 के सेंसस के लिए डीएफओ ने विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां ड्रोन से हवाई निगरानी पर जोर दिया गया। पूरी प्रक्रिया में 3 से 7 दिन लगते हैं फील्ड वर्क के लिए, लेकिन डेटा विश्लेषण, सत्यापन और रिपोर्टिंग में 6 से 12 महीने लग सकते हैं। मान्यता राज्य वन विभाग और एमओईएफसीसी देते हैं, जो इसे राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करते हैं।

दलमा में हालिया गणना से पता चला कि हाथियों की संख्या घटकर 10 के आसपास रह गई है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि हाथी स्थायी निवासी नहीं, बल्कि प्रवासी हैं। वे दलमा से सारंडा जंगल या पश्चिम बंगाल के पांचेत फॉरेस्ट डिवीजन तक 100-200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसलिए, "घटना" का मतलब मृत्यु नहीं, बल्कि माइग्रेशन हो सकता है। फिर भी, इलेक्ट्रोक्यूशन और मानव-हाथी संघर्ष से कुछ मौतें दर्ज हुई हैं। 2024-25 में झारखंड में 23 हाथियों की मौत हुई, जिनमें दलमा के भी शामिल थे।

30 वर्षों का सफर: चरमोत्कर्ष से संकट तक

बीते तीन दशकों में दलमा की हाथी आबादी एक रोलरकोस्टर की सवारी कर चुकी है। 1990 के दशक में जब अभ्यारण्य की स्थापना (1975) के बाद जंगल घने थे, आबादी 50-60 के आसपास स्थिर थी। लेकिन 2001 में "बेबी बूम" आया। 82 हाथी गिने गए, जिनमें 10 नए नन्हें हाथी थे। कारण? अच्छा हैबिटेट मैनेजमेंट और कम मानवीय हस्तक्षेप। 2010-12 में वृद्धि जारी रही। 2009 के 90 से बढ़कर 2012 में 119 हो गए, जिसमें 13 नए मेहमानों की मौजूदगी ने खुशी लहर दौड़ा दी। यह चरम था। सबसे ज्यादा संख्या। लेकिन इसके पीछे थे वन विभाग के प्रयास के तहत जल संरक्षण और घास के मैदान विकसित करना था। फिर आया पतन। 2019 में 66, 2022 में 105 (अस्थायी उछाल), लेकिन 2023 में 88 और 2024 में यह संख्या घट कर मात्र 85 पर आ गई। 2025 में कोर क्षेत्र में मात्र 10 हाथी पाये जाए हैं। सबसे कम 2025 का ही है। कारण? प्राथमिक रूप से हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन खनन, सड़कें और सब्जी खेती ने कॉरिडोर तोड़े। दलमा-चांडिल कॉरिडोर में सुवर्णरेखा नहर और रेलवे लाइन ने बाधा डाली। दूसरा, मानव-हाथी संघर्ष। झारखंड में 23 वर्षों में 400 से अधिक मौतें हुईं, ज्यादातर इलेक्ट्रिक वायरिंग से। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से सूखा, जो प्रवास को मजबूर करता है। हाथी आते-जाते रहते हैं, लेकिन मृत्यु दर बढ़ी है। व्यस्क नर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ये आंकड़े नेशनल एलीफैंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट और डब्ल्यूआईआई के रिपोर्ट्स से लिए गए हैं, जो दिखाते हैं कि दलमा अब "ट्रांजिट पॉइंट" बन चुका है, न कि स्थायी घर।

वन विभाग की कोशिशें: उम्मीद की किरणें

हाथी की आबादी बढ़ाने के लिए झारखंड वन विभाग ने कई कदम उठाए हैं। 2010 के दशक से प्रोजेक्ट एलीफैंट के तहत दलमा को

प्राथमिकता मिली। सबसे बड़ा प्रयास हैबिटेट रिस्टोरेशन एक लाख पेड़ लगाए गए कॉरिडोर को जोड़ने के लिए, जैसे ग्रो-ट्रीज प्रोजेक्ट में महुआ और साल के पौधे। इससे फल-फूल उपलब्ध होकर हाथियों का आकर्षण बढ़ा।

इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधारः इलेक्ट्रिक फेंस और रबल वॉल्स लगाए गए संघर्ष क्षेत्रों में। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स से 20 नए जलाशय बने, जो गर्मी में हाथियों को लुभाते हैं। घास प्लॉट डेवलपमेंट से चारा उपलब्धता सुधरी। तकनीकी मोर्चे पर, अबुआ हाथी ऐप लॉन्च हुआ। यह किसानों को हाथी झुंड की लोकेशन अलर्ट करता है, संघर्ष कम करने के लिए। जागरूकता के लिए 5 अक्टूबर 2025 को “रन फॉर गजराज” हॉफ मैराथन आयोजित की, जिसमें 4,000 लोग शामिल हुए। विश्व हाथी दिवस पर 13 अगस्त को कॉरिडोर संरक्षण पर वर्कशॉप हुए।

विशेषज्ञों की राय: चिंता और सुझाव

दलमा के डीएफओ सबा आलम ने हालिया सेंसस के बाद कहा कि संख्या में उतार-चढ़ाव सामान्य है, क्योंकि हाथी 50-100 किलोमीटर के दायरे में घूमते हैं। लेकिन हम माइग्रेशन ट्रैकिंग पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सेंसस ड्रोन से ज्यादा सटीक होगा।” वे मानते हैं कि मृत्यु दर कम करने के लिए फेंसिंग जरूरी है, लेकिन कॉरिडोर जोड़ना प्राथमिकता।

वन्यजीव विशेषज्ञ **प्रसेनजीत सरकार** लंबे समय से दलमा से जुड़े रहे, अधिक सख्त हैं। अब खनन ने जंगल काटे। हाथी मर नहीं रहे, लेकिन भटक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ओर। 2001 में बेबी बूम देखा गया है। तब मादा हाथी दूध पिलाने आती थीं। अब डर है। विभाग ने अच्छा किया, लेकिन इको-टूरिज्म बढ़ाकर आय रुट बनाएं, हाथी सफारी से। दलमा के हाथी न केवल एक प्रजाति हैं, बल्कि पारिस्थितिकी का प्रतीक। उनकी संख्या घटना दुखद है, लेकिन माइग्रेशन की वजह से उम्मीद बाकी है। बड़े पैमाने पर कॉरिडोर रिस्टोरेशन और समुदाय जागरूकता जरूरी है। ■

मूवमेंट के कारण बदल रहा है ठिकाना : मुख्य वन संरक्षक

दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की घटती संख्या को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) **एसआर. नटेश** ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि दलमा में हाथियों की संख्या घट रही है, बल्कि हाथियों का प्राकृतिक स्वभाव ही लगातार मूवमेंट करना है। वे मौसम, भोजन और पानी की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए कई बार दलमा क्षेत्र में कम दिखते हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग हाथियों के संरक्षण और उनके अनुकूल पर्यावरण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। दलमा में भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। कई जलस्रोतों का पुनर्जीवित किया गया है और हाथियों को वापस दलमा की ओर आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्य वन संरक्षक ने माना कि पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र में खोदे गए ट्रेंच और लगाए गए सोलर फेंसिंग हाथियों की आवाजाही में बाधक बने हैं। कई हाथी इन अवरोधों के कारण दलमा लौट नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब उनका मूवमेंट चाईबासा, खूंटी, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के जंगलों की ओर अधिक देखा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विभाग बंगाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है ताकि हाथियों के पारंपरिक रास्ते फिर से खुले और उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। नटेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दलमा हाथियों का स्थायी निवास स्थल बने रहे, और इसके लिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। ■

खतरे में जगुआर

▪ दीपक कुमार शर्मा

जगुआर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपने निवास स्थान पर खाद्य शृंखला में संतुलन करते हैं तथा अन्य प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। जगुआर के संकटग्रस्त होने का प्रमुख कारण उनके आवास विनाश और विखंडन है।

जगुआर की आबादी तेजी से घट रही है। बीते 21 सालों में इनकी संख्या में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है, जो चिंताजनक है। इनके संकटग्रस्त होने की प्रमुख वजह बढ़ते आवास संकट, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष हैं। यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है।

जगुआर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपने निवास स्थान पर खाद्य शृंखला में संतुलन करते हैं तथा अन्य प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। जगुआर के संकटग्रस्त होने का प्रमुख कारण उनके आवास विनाश और विखंडन है। जगुआर मुख्य रूप से रात के समय सक्रिय रहते हैं और जीवित रहने के लिए उन्हें बहुत अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, वनों की कटाई और कृषि गतिविधियां जगुआर के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रही हैं, जिससे उनकी सीमा धीरे-धीरे कम हो रही है।

जगुआर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपने निवास स्थान पर खाद्य शृंखला में संतुलन करते हैं तथा अन्य प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। जगुआर के संकटग्रस्त होने का प्रमुख कारण उनके आवास विनाश और विखंडन है।

हालात नहीं बदले तो आ सकते हैं असुरक्षित श्रेणी में

आईयूसीएन इनकी स्थिति की जांच में जुटा है और यदि अवैध शिकार और निवास स्थान का नुकसान जारी रहा तो उन्हें जल्द ही असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। संघ का कहना है कि जगुआर केंद्रित संरक्षण रणनीति सह-अस्तित्व वाली प्रजातियत्र के रूप में काम कर सकती है, इसलिए जगुआर के संरक्षण के लिए तत्काल उचित रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। ▪

उत्तर में ठंड की समय से पहले दस्तक

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में कई ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार सक्रिय हैं, जिनका असर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और तटीय इलाकों में देखा जा रहा है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण अगले तीन दिनों तक कई जगहों पर बारिश के दौर के जारी रहने का पूर्वानुमान है।

▪ दयानिधि

असम और उसके आसपास के इलाकों, दक्षिण बांग्लादेश और उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रसार बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व अरब सागर, हरियाणा-उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के आस-पास भी अलग-अलग स्तरों पर प्रसार सक्रिय हैं। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और आसपास के इलाकों तथा उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उससे सटे हिस्सों में एक चक्रवाती प्रसार के रूप में में सक्रिय है।

मौसम विभाग के अनुसार, मौसमी गतिविधियों की वजह से देश के दक्षिणी, तटीय और पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना बनी हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा ओडिशा में भी गरज के साथ बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। इन राज्यों में 64.5 से 115.5 मिमी तक बरस सकते हैं बादल। विभाग ने यहां बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज

उत्तर भारत में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व इससे सटे एनसीआर में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों पर समय से पहले हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। दिल्ली में 10 अक्टूबर को पहली बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में 12 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और उस दिन तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2023 में तीन अक्टूबर को ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं 2025 में दिल्ली में अधिकतम तापमान के 31 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान के 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मूंगफली, मक्का, काली मिर्च, इलायची, हल्दी और कॉफी की कटाई की हुई उपज को सूखे, ढकर और हवादार जगहों पर रखने का सुझाव दिया है। जबकि धान, मक्का, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, केला, नारियल और सुपारी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की सलाह दी है ताकि जलभराव न होने पाए।

विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, हल्दी, सब्जियां और नारियल, सुपारी, केला, कॉफी तथा काली मिर्च के बागानों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी है। तटीय कर्नाटक में धान और नारियल-सुपारी की खेती वाले इलाकों से अतिरिक्त पानी तुरंत निकालें ताकि फसलों की जड़ें सड़ें नहीं।

असम और मेघालय की बात करें तो यहां किसानों को असम में पकी हुई सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, बैंगन आदि को तुरंत खेतों से निकालने को कहा गया है ताकि भारी बारिश से नुकसान न हो। साली धान, उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं, मेघालय में खड़ी फसलों, सब्जियों और फलों के बगीचों में पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मौसम विभाग ने ओडिशा में धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, कपास और सब्जियों के खेतों में जलभराव न होने देने की सलाह दी है। विभाग ने यह भी कहा है कि जिन खेतों में जलभराव हो गया है, वहां तुरंत नालियां बनाकर पानी बाहर निकालें।

मानसून की वापसी की प्रक्रिया हुई तेज

मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे देश से विदा ले रहा है। आने वाले दो से तीन दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष हिस्सों से भी लौटने की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से भी मानसून की वापसी की स्थिति बन रही है। इससे यह स्पष्ट है कि अक्टूबर के आखिरी तक देश के ज्यादातर हिस्सों से मानसून पूरी तरह विदाई ले लेगा।

11 अक्टूबर 2025 को देश के दक्षिणी, तटीय और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसमी गतिविधि काफी सक्रिय रहेगी। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के दौर देखने को मिल सकते हैं।

तापमान में उतार-चढ़ाव

देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल, 10 अक्टूबर, 2025 को तमिलनाडु के मदुरै में अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि कल, देश के मैदानी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के मंडी में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ■

क्या इस बार समय से पहले ही आ गई सर्दी?

भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण कई राज्यों में ठंडक का अहसास शुरू हो गया है। इसलिए उत्तर भारत में सर्दी जल्दी आने की उम्मीद है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

मौसम में अचानक आए परिवर्तन से निर्धारित समय से काफी पहले ही हवा में ठंडक आ गई है। इस मौसम में पहली बार दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में भयंकर बारिश हुई है। इसलिए उत्तर भारत में सर्दी के जल्दी आने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को ऊंचाई वाले इलाकों में पहली बर्फबारी के बाद रात भर बर्फबारी जारी रही। जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं, हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई।

सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद

पूर्वोत्तर मानसून सीजन (अक्टूबर-दिसंबर) भी सामान्य से अधिक बारिश वाला रहने की उम्मीद है। विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में, जहां वर्षा एलपीए के 112% से अधिक हो सकती है। जबकि मध्य और दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों में मानसून के बाद के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत जिसमें वर्तमान में वर्षा वाले मैदानी भाग भी शामिल हैं। इन इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी वर्तमान मौसम गतिविधि और आगामी मौसमी प्रवृत्तियों का श्रेय मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में गिरावट के कारण उत्पन्न होने वाली ला नीना स्थितियों को देते हैं।

अक्टूबर-दिसंबर में ला नीना होने की है 71% संभावना

अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार, वर्तमान में तटस्थ एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के बीच ला नीना विकसित होने की 71% संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक एम. महापात्रा ने कहा कि आमतौर पर, ला नीना के कारण सर्दियों में तापमान सामान्य से कम रहता है। हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि अक्टूबर में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। ■

आनंद सिंह की दूसरी पुस्तक ‘समय के साथ’ का विधायक सरयू राय ने किया लोकार्पण

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

विगत 3 अक्टूबर को जमशेदपुर के मिलानी हॉल में आयोजित एक समारोह में पर्यावरण पर केंद्रित मासिक पत्रिका ‘युगांतर प्रकृति’ के संरक्षक और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने ‘युगांतर प्रकृति’ के प्रधान संपादक आनंद सिंह की दूसरी पुस्तक ‘समय के साथ’ का लोकार्पण किया। इस मौके पर हिंदी दैनिक प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र, न्यू इस्पात मेल के संपादक ब्रज भूषण सिंह, चमकता आईना के संपादक जय प्रकाश राय, बिहार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव मौजूद रहे। सरयू राय ने पुस्तक की सराहना की और कहा कि इसमें कई सूचनाएं हैं। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उन्हें कई नई जानकारियां मिलेंगी। पुस्तक में किसी की नुक्ताचीनी नहीं की गई है। यह पुस्तक सकारात्मक नजरिये से लिखी गई है जिसकी समाज को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ■

गड्ढे से जंगल की रानी बनी रजनी, दलमा में मनाया गया यादगार जन्मदिन उत्सव

युगांतर प्रकृति नेटवर्क

दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी की स्टार मादा हाथी रजनी का 16वां जन्मदिन बीते सात अक्टूबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वन विभाग ने इस मौके को खास बनाने के लिए ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ एक यादगार समारोह आयोजित किया। बच्चों की तालियों और बैंड की धुनों के बीच जब रजनी मंच पर आई, तो पूरा दलमा जंगल जैसे जीवंत हो उठा।

रेंज अफसर दिनेश चंद्रा ने बताया कि रजनी की कहानी जितनी भावुक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। करीब 13 साल पहले नीमडीह प्रखंड के जंगलों में यह मादा हाथी का बच्चा गड्ढे में गिरा मिला था। झुंड से बिछड़कर घायल हुई रजनी को वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत से रेस्क्यू किया था। तीन महीने तक उसका इलाज टाटा जू में चला, जिसके बाद उसे दलमा लाकर प्यार और देखभाल से पाला गया। "तब से वह हमारे परिवार का हिस्सा है।

आज रजनी दलमा की पहचान बन चुकी है। मकूलाकोचा स्थित उसका स्थायी आवास पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जो भी दलमा पहुंचता है, सबसे पहले रजनी से मुलाकात करता है। बच्चे उसकी सूंड पर हाथ फेरते हैं, पर्यटक उसके साथ सेल्फी लेते हैं, और फिर जंगल सफारी पर निकलते हैं।

इस बार रजनी के जन्मदिन पर 16 पाउंड का केक काटा गया, जिसे बच्चों में बांटा गया। समारोह के दौरान रजनी भी बेहद खुश नजर आई। बच्चों के साथ खेलती, सूंड से गुब्बारे उड़ाती और केक खाते हुए उसने सबका दिल जीत लिया। वन कर्मियों का कहना है कि रजनी सिर्फ एक हाथी नहीं, दलमा की आत्मा है। उसकी मौजूदगी यहां के पर्यावरण और लोगों के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बन चुकी है। ■

दुनिया की सबसे जहरीली मछलियां

हम लोग लगातार पढ़ते रहे हैं कि मछली जल की रानी है। मछली वास्तव में जल की रानी है। यह अपने आस-पास के माहौल को सही रखती है। मछली से इंसानों का रिश्ता भी बेहद गहरा है। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो मछली पालन करते हैं। मछलियां स्वभाव से बेहद शांत होती हैं लेकिन सभी मछलियां शांत नहीं होतीं। इनमें तो कुछ इतनी जहरीली होती हैं कि इंसान को काट लें तो इंसान क्षण भर में मर जाए। *दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक मछलियां इस प्रकार हैं:*

स्टोनफ़िश

इसे दुनिया की सबसे जहरीली मछली माना जाता है। यह समुद्र की चट्टानों के बीच छुपी रहती है और अगर कोई गलती से इस पर पैर रख दे, तो यह एक बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ती है, जो जानलेवा हो सकता है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के तटीय इलाकों में पाई जाती है।

पिरान्हा

यह अपनी नुकीली और धारदार दांतों के लिए जानी जाती है। दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली यह मछली, खासकर जब झुंड में होती है और भूखी होती है, तो बेहद आक्रामक हो सकती है और कुछ ही मिनटों में अपने शिकार का कंकाल बना सकती है।

इलेक्ट्रिक ईल

यह वास्तव में एक मछली है, जो अपने शरीर से 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है। इतना शक्तिशाली झटका किसी भी इंसान को बेहोश करने या मार डालने के लिए काफी है। यह अमेज़न और ओरिनोको नदियों के बेसिन में पाई जाती है।

शार्क

शार्क की कुछ प्रजातियां, जैसे कि टाइगर शार्क और बुल शार्क, मनुष्यों के लिए खतरनाक मानी जाती हैं। ये उथले पानी में भी शिकार करती हैं, जिससे इंसानों के साथ उनका सामना हो सकता है। हालाँकि, आम धारणा के विपरीत, शार्क के हमले दुर्लभ ही होते हैं।

पफर फिश (फुगु)

जापान में पाई जाने वाली यह मछली दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। इसके अंगों में एक घातक जहर होता है, जो खाने पर जानलेवा हो सकता है। इसे खाने के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले शेफ की आवश्यकता होती है।

लायनफ़िश

अपनी रंगीन धारियों और पंखों के लिए सुंदर दिखने वाली यह मछली जहरीली होती है। इसके कांटेदार पंखों में शक्तिशाली जहर होता है, जिसका डंक बहुत दर्दनाक होता है, हालांकि यह आमतौर पर घातक नहीं होता है।

मोरय ईल

यह सांप जैसी दिखने वाली मछली चट्टानों और गुफाओं में छिपी रहती है और शिकारी होती है। इसके नुकीले दांत होते हैं और जब यह हमला करती है तो गंभीर घाव कर सकती है।

रतन टाटा, अमिताभ बच्चन और शिबू सोरेन की पेंटिंग बना कर भी मैं जमीन पर हूं-अर्जुन दास

मेरा नाम अर्जुन दास है। मैं सोनारी जमशेदपुर का रहनेवाला हूं। मैं जब छोटा था तो टीवी पर कार्टून आता था तो उसे देखकर मैं कार्टून बनाता था। जब मैं 12-13 साल का था तो उसे और अच्छा करने लग गया। वाटर कलर वगैरह का प्रयोग करने लगा। जब मैं 20 का हुआ तो जमशेदपुर में एक वर्कशॉप लगा। बड़े-बड़े महान कलाकार आए थे। मैं देखने जाता था। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि कैनवास पर कौन सा कलर यूज होता है, कैसे काम किया जाता है। कोई जानकारी नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में पता था वाटर कलर और पेपर। बस इसी चीज को मैं जानता था।

एक मैडम थी टाटा स्टील में। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे भी इस लेवल पर बैठना है। मैडम ने मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मेरा नाम अर्जुन दास है, मैं भी कलाकार हूं। फिर मैडम ने कहा कि मैं देखती हूं। उस समय टाटा स्टील के कुछ ऑफिसर्स ने मैडम से मेरे बारे में सिफारिश की। मैडम बोली ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम चांस देती हूं। टाटा स्टील के एक ऑफिसर थे संजीव कौल। उनसे मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे बैठने का एक मौका दिया जाए। सर ने फिर मैडम से बात की और कहा कि एक बार चांस दे दीजिए। फिर मैडम ने यहां से मुझे रायपुर भेजा। वहां पर जब संजीव कॉल चीफ गेस्ट बन करके आये तो वहां उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा कि अर्जुन जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इस पर मैंने कहा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। काम कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल। वहां महान कलाकार थे। उन लोगों के सामने मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने वहां बुद्ध की पेंटिंग बनायी। वह मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम हुआ। उसे काफी लोगों ने वहां पसंद किया। सारे बड़े-बड़े कलाकार जो थे, उन्होंने काफी पसंद किया जबकि मुझे काफी डर लग रहा था और अंदर से मैं डरा हुआ था। वहां हमें सफलता मिली। इस तरह से मैं काम शुरू किया।

शिबू सोरेन जी को मैंने पहली बार देखा एक आर्ट कंपटीशन में। तब मैं 14 साल का था। मैं जानता नहीं था कि शिबू सोरेन कौन हैं? बस टीवी और अखबारों में देखा था। मुझे लगा लगा कि सर से एक बार जरूर मिलूं और एक पेंटिंग गिफ्ट करूं। मेरे एक मित्र हैं जो समाज सेवा करते हैं। उन्होंने कुणाल षाडंगी से मेरी बात कराई। फिर कुणाल षाडंगी ने हमें रांची बुलाया। वहां प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई। हेमंत सोरेन पेंटिंग देख कर भावुक हो गए। उनकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। पेंटिंग को देखते ही रह गये। मैंने पूछा-सर पेंटिंग कैसी है? उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहाः बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। बहुत खूबसूरत बना है। दिल जीत लिया आपने।

मैंने 2021 में पदम विभूषण रतन टाटा जी की पेंटिंग बनाई। उसे लेकर मैं मुंबई गया और शांतनु नायडू से मिला। उन्होंने रतन टाटा से मेरी मुलाकात करवाई। रतन टाटा सर को गेट खोलते हुए मैंने देखा। रतन टाटा सर ने हमें अंदर आने के लिए बोला। मैं अंदर गया और मुझे सोफा पर बैठाया। मैंने सर को पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद रतन टाटा सर चेयर लेकर बिल्कुल मेरे सामने बैठ गए। रतन टाटा सर ने कहा कि मुझे पता चला कि आप मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, तो मुझे काफी खराब लगा। मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने पेंटिंग देखी। काफी देर तक वह पेंटिंग को बहुत गौर से देखते रहे। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं जमशेदपुर में रहता हूं। फिर उन्होंने पूछा जमशेदपुर में आप कहां रहते हैं। मैंने कहा सर मैं जमशेदपुर में सोनारी में रहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं वहां जाता रहता हूं। मैं कदमा में भी जाता था।

सर, मेरी विधा में मां सरस्वती की कृपा और मेरा कर्म भी अहम है। किस्मत ने मेरा हमेशा से बहुत साथ दिया है। मैंने अमिताभ बच्चन की भी पेंटिंग बनाई है। उन्हें गिफ्ट भी किया है।

मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। पेंटिंग बनाने में समय तो लगता है, लेकिन फिर भी दो-तीन दिन में एक पेंटिंग तैयार कर देता हूं। कोई पेंटिंग हफ्ते भर में तैयार होता है। किसी-किसी में 10 दिन भी लग जाता है। इंसान को हमेशा जमीन पर ही रहना चाहिए। ■

(जैसा **अर्जुन दास** ने युगांतर प्रकृति के प्रधान संपादक **आनंद सिंह** से बातचीत में कहा)

गौर से पढ़िए

युगांतर प्रकृति

हमारे **20 सवालों** के जवाब दीजिए

और, पाइए आकर्षक पुरस्कार

पढ़ो और पुरस्कार पाओ

प्रथम पुरस्कार-501 रुपये नकद

द्वितीय पुरस्कार-351 रुपये नकद

तृतीय पुरस्कार-251 रुपये नकद

नियम और शर्तें

1. आपको युगांतर प्रकृति का यह अंक बेहद गौर से पढ़ना है।
2. इसी अंक में प्रकाशित विभिन्न लेखों से हम 20 सवाल करेंगे। उन 20 सवालों के जो सही-सही जवाब देंगे, उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
3. अगर 20 में से 20 सवालों के सही जवाब कई लोग देते हैं तो पुरस्कार उन्हें मिलेगा, जिनका जवाब सबसे पहले आएगा। यानी, जो पहले जवाब देंगे, वो पुरस्कार के हकदार होंगे।
4. जवाब सिर्फ ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। ई-मेल आईडी है yugantarprakriti@gmail.com
5. कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, एक रंगीन फोटो, बैंक खाता अथवा यूपीआई आईडी अथवा क्यूआर कोड अवश्य भेजें।
6. विजेताओं को धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी और अगले अंक में उनकी तस्वीर के साथ उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
7. इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। उम्र, लिंग का कोई बंधन नहीं है।
8. इस प्रतियोगिता में युगांतर प्रकृति परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते।
9. निर्णायक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। उसे किसी भी सूरत में, कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

1. अर्जुन दास कहां के रहने वाले हैं और क्या करते हैं?
2. अमिताभ बच्चन, रतन टाटा आदि की पेंटिंग्स किसने बनाई है?
3. पारिस्थितिकी क्या है?
4. पारिस्थितिकी में सांस का काम कौन करता है?
5. नवंबर में पर्यावरण की दृष्टि से अहम कितने दिन हैं?
6. समय के साथ पुस्तक का लोकार्पण किन्होंने किया?
7. पिरान्हा क्या है?
8. दुनिया की सबसे जहरीली मछली कौन है, जिसके काटने से इंसान मर जाता है?
9. रजनी कौन है, जिसका अभी जन्मदिन मनाया गया?
10. उत्तर भारत में समय से पहले ठंड क्यों पड़ने लगी है?
11. मोथा क्या है?
12. जगुआर दिवस कब मनाया जाता है?
13. भारत में जगुआर की क्या स्थिति है?
14. दुनिया में सबसे ज्यादा जगुआर कहां पाये जाते हैं?
15. दलमा में हाथियों की संख्या बढ़ी है या घटी है?
16. दलमा किस जिले में पड़ता है?
17. चांदे बाबा तालाब कहां है और क्यों चर्चित है इन दिनों?
18. झारखंड के किस राज्य में अवैध खनन हो रहा है, जिससे एनजीटी खफा है?
19. इजरायल और गाजा के बीच युद्ध में कितने प्रतिशत वृक्ष नष्ट हो गये?
20. अस्थमा वाला इनहेलर पर्यावरण के लिए खतरनाक कैसे है?

युगांतर भारती

ने पर्यावरण को जन आंदोलन बना दिया। इसके लिए युगांतर भारती को बधाई। वास्तव में इस संस्था ने बढ़िया काम किया है।

-श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्यपाल, झारखंड

5 जून 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय ने बोकारो के तेलमच्चो में युगांतर भारती के बारे में जो बोला, उसके पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। वह संघर्ष हमारा साथी है। उसी संघर्ष की राह पर हमें आगे भी चलना है और हम संघर्ष करेंगे।

जीरो एरर, 100% सटिस्फैक्शन हमारी पहचान है।

NABL
National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories
CERTIFICATE OF ACCREDITATION
YUGANTAR BHARATI ANALYTICAL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
has been assessed and accredited in accordance with the standard
ISO/IEC 17025:2005
for its facilities at
Sosai, P.O. & P.S. - Namkum, Ranchi, Jharkhand
in the discipline of
BIOLOGICAL TESTING

Certificate of Registration
YUGANTAR BHARATI ANALYTICAL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
Standard: ISO 9001:2008 (QMS)

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

युगांतर भारती

भरोसा जीतने का माद्दा

युगांतर न्यूज
एक ऐसा न्यूज पोर्टल जिसमें आपको मिलेंगी
राजनीति, हेल्थ और पर्यावरण की खबरें
www.yugantarnews.in पर पढ़ें
हमारा YouTube Channel देखें yugantarnews

With Best Compliments From
दामोदर बचाओ आंदोलन